● वर्ष-5

● अंक-305

रायपुर, शनिवार
08 अगस्त 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6>> ऐसे आंखों की देखभाल...

केंद्र सरकार की बड़ी मंजूरी

राजनांदगांव में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब

- ईएमसी 2.0 परियोजना से 3,000 करोड़ रु. से अधिक निवेश का रास्ता खुलेगा
- 9,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी2.0) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य को मिली यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ को देश के उभरते इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्रों की श्रेणी में लाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। इस परियोजना से राज्य में 3,000 करोड़ रु. से अधिक के निवेश का मार्ग खुलेगा और लगभग 9,000 युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 432.08 करोड़ रु. की इस परियोजना के लिए 210.56 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता

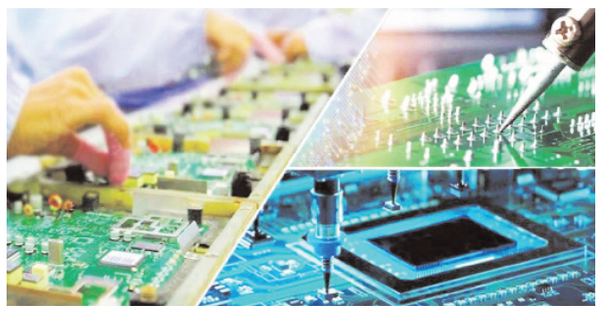

स्वीकृत की है। परियोजना का विकास छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम करेगा। लगभग 306 एकड़ में विकसित होने वाले इस क्लस्टर में रेडी-बिल्ट फैक्ट्री, आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, बिजली, पानी, वेयरहाउस और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि कंपनियां कम समय में उत्पादन शुरू कर सकें। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की चार प्रमुख कंपनियां पहले ही यहां निवेश में रुचि जता चुकी हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ में निवेश के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षित करेगी, ताकि नए उद्योगों में रोजगार का अधिकतम लाभ प्रदेश के युवाओं को मिल सके।

छत्तीसगढ़ देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल

'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के विज़न को आगे बढ़ाने वाली यह परियोजना इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, कंपोनेंट निर्माण और वैल्यू एडिशन को नई गति देगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल होगा, जहां भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव रखी जा रही है।

मोदी ने बागी टीएमसी सांसदों से कहा-

वे क्या कहते हैं, इसकी चिंता न करें, मैं आपके साथ हूँ

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बागी सांसदों को भरोसा दिलाया कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खबरों के मुताबिक, उन्होंने कहा कि आपके बारे में क्या कहा जा रहा है, इसकी चिंता न करें। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ।

यह बैठक मॉनसून सत्र के दौरान संसद में हो रहे नए गठबंधनों के बीच विपक्ष के पूर्व सांसदों का स्वागत करने और उन्हें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल करने के लिए बुलाई गई थी। इस बैठक में लगभग 45 सांसद शामिल हुए। इनमें टीएमसी के 20 बागी सांसद उद्धव सेना के सात पूर्व सांसद (जिनमें से छह आधिकारिक तौर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए), नेशनल पीपल्स पार्टी के 20 सांसद और एनसीपी (अजित पवार गुट) के दो सांसद शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के सांसदों से लोगों के बीच अपनी पहुँच बढ़ाने को कहा और कहा कि देश की तरक्की के लिए राज्य की तरक्की बहुत ज़रूरी है। बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार, हर सांसद को उनके सोशल मीडिया पर लोगों से जुड़ाव की जानकारी वाला एक प्रिंटआउट दिया गया और प्रधानमंत्री ने उनसे लोगों के साथ डिजिटल जुड़ाव बढ़ाने को कहा। मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि जब बंगाल तरक्की करता है, तो भारत तरक्की करता है और सांसदों से कहा कि राज्य में अभी बहुत काम करना बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि विकास सिर्फ़ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों को भी बेहतर कनेक्टिविटी और तेज़ी से विकास की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने सांसदों को सालाना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह भी दी और कहा कि आगे के बड़े काम को देखते हुए उन्हें फिट रहने की जरूरत है।

चाय के दौरान बैठक में कुछ हल्के-फुल्के पल भी आए। जब माचा चाय परोसी गई, तो बीजेपी सांसद शताब्दी रॉय ने प्रधानमंत्री को बताया कि यह क्या है और कहा कि यह पश्चिम बंगाल में भी मिलती है। मोदी ने फिर से कहा कि बंगाल को भारत की तरक्की में अपनी अहम भूमिका फिर से हासिल करनी चाहिए; उन्होंने कहा कि जब राज्य ने पहले तरक्की की थी, तो देश ने भी तरक्की की थी। बातचीत के दौरान हंसी-मज़ाक का माहौल तब बना जब सीनियर सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री कई ऐसे नेताओं से घिरे हुए हैं जो पहले एक्टर थे- इनमें शताब्दी रॉय, सयोनी घोष, जून मालिया और रचना बनर्जी शामिल हैं। उन्होंने मज़ाक में कहा कि उनके साथ बने रहने के लिए प्रधानमंत्री को भी फिट रहना होगा।

मुख्यमंत्री ने हैंडलूम ब्रांड 'कोशल फैब' लॉच किया

आत्मसमर्पित महिलाओं का रैंप वॉक आकर्षण का केंद्र

कार्यक्रम का सबसे प्रेरक और भावनात्मक क्षण वह रहा, जब बस्तर की आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं ने स्वदेशी फैशन शो में आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कोसा सिल्क एवं अन्य हैंडलूम परिधानों का आकर्षक प्रदर्शन किया।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शुक्रवार को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन एवं स्वदेशी प्रदर्शनी में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने रेशम, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी एवं माटीकला बोर्ड के विभिन्न हितग्राहियों तथा मेधावी छात्र-छात्राओं को 10 करोड़ 90 लाख रुपये से अधिक की अनुदान एवं पुरस्कार राशि वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ के नए प्रीमियम हैंडलूम ब्रांड कोशल फैब का शुभारंभ करते हुए उसके लोगो एवं कैटलॉग का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने हथकरघा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का भी शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों, विशेषकर बुनकरों एवं शिल्पकारों को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुभकामनाएँ दीं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ का कोसा, बस्तर की बुनाई तथा प्रदेश के पारंपरिक हथकरघा उत्पाद देश-दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के हथकरघा उत्पादों को लोकल टू ग्लोबल की नई पहचान दिलाना है। इसके लिए आधुनिक डिज़ाइन, कौशल

उन्नयन, प्रशिक्षण, ब्रांडिंग, विपणन तथा नए बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। । कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ के नए प्रीमियम हैंडलूम ब्रांड कोशल फैब का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ब्रांड के लोगो एवं कैटलॉग का विमोचन भी किया। लूम टू लग्जरी की अवधारणा पर आधारित यह प्रीमियम ब्रांड छत्तीसगढ़ के कोसा एवं पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान दिलाने तथा उन्हें वैश्विक स्तर तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ द्वारा एनआईसी के सहयोग से विकसित इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया गया। इस डिजिटल पहल से उत्पादों के भंडारण, प्रबंधन, विपणन तथा वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने खरीदी कोसा साड़ी

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वदेशी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ, बिलासा हैंडलूम, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, हस्तशिल्प विकास बोर्ड, सबरी एम्पोरियम तथा माटीकला बोर्ड सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को अधिकाधिक अपनाने और प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। प्रदर्शनी के दौरान उन्होंने हथकरघा स्टॉल से स्वयं तत्काल भुगतान कर कोसा साड़ी खरीदी।

प्रमुख समाचार

सीजेपी में भाई-भतीजावाद हावी? कोर कमेटी के गठन पर फूटा गुस्सा

मुंबई। भारतीय राजनीत में परिवारवाद और भाई-भतीजावाद कब किस संगठन में हावी हो जाए पता ही नही चलता। अमूमन राज्य के सभी राजनीतिक दलों पर ये आरोप लगते रहते हैं। अब हाल ही में बने छात्रों के हित में सीजेपी संगठन पर भी यही आरोप लग रहे हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की कोर कमेटी को लेकर विवाद सामने आया है। अभिजीत दीपके के घर के बाहर पहुंचे कुछ युवाओं ने पार्टी नेतृत्व पर परिवारवाद और पक्षपात के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही जंतर-मंतर छात्र आंदोलन से जुड़े सभी कोऑर्डिनेटर्स को प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का दावा है कि वे जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन की शुरुआत से ही सक्रिय रहे और आंदोलन में कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाई। आरोप है कि हाल ही में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में केवल अभिजीत दीपके के करीबी और पहचान वाले लोगों को बुलाया गया जबकि आंदोलन से जुड़े कई कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दिया गया।

संसद में घमासान के आसार- कांग्रेस ने पार्टी सांसदों को जारी किया व्हिप

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के बीच राजनीतिक सरगर्मियां अचानक तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में अपने सभी सांसदों को उपस्थित रहने का फरमान जारी किया है। पार्टी ने राज्यसभा और लोकसभा के अपने सदस्यों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। इसके तहत सभी सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। पार्टी के अनुसार इन तीन दिनों में बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को भी एकजुट करने की कवायद शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने इंडिया गठबंधन के सभी साथी दलों से भी संपर्क किया है। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इन तीन दिनों के दौरान अपने सांसदों की सौ फीसदी मौजूदगी सुनिश्चित करें। पिछले दिनों संसद की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे हमलावर दिखे थे। उन्होंने छात्र आंदोलन पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब विवादास्पद एफसीआरए संशोधन विधेयक पर चर्चा की खबरें आ रही हैं।

छात्रों और सरकार के बीच वार्ता खत्म सीबीआई जांच पर सहमति नहीं

रांची। झारखंड में जेपीएससी-जेएसएसई समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और सीबीआई जांच की मांग को लेकर जारी छात्रों के सत्याग्रह आंदोलन के 14वें दिन शुक्रवार को सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच महत्वपूर्ण वार्ता हुई।

रांची स्थित राजकीय अतिथिशाला में करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में छात्रों की विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। हालांकि, आंदोलन की सबसे अहम मांग सीबीआई जांच पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। ऐसे में छात्रों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक इस मांग पर फैसला नहीं होता, तब तक उनका सत्याग्रह आंदोलन जारी रहेगा। बैठक के बाद छात्र नेता रविंद्र पासवान ने बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा कि सरकार के साथ यह उनकी पहली औपचारिक बैठक थी।

उन्होंने कहा कि चर्चा का माहौल बेहद सकारात्मक रहा और सभी के साथ बैठकर ऐसा महसूस हुआ जैसे परिवार के बीच बातचीत हो रही हो। रविंद्र पासवान ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सभी मंत्री उनकी मांगों को वास्तविक मानते हुए उन पर गंभीरता से विचार करेंगे।

नीट-यूजी पेपर लीकः सोसायटी एप बना अहम सबूत

नई दिल्ली। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में दाखिल चार्जशीट में कई डिजिटल और फोरेंसिक सबूतों का जिक्र किया है। इनमें पुणे की एक रिहायशी सोसायटी के एंट्री मैनेजमेंट एप का रिकॉर्ड भी शामिल है। इसी सोसायटी में एनटीए के केमिस्ट्री विषय के विशेषज्ञ और आरोपी पीवी कुलकर्णी रहते थे।

सीबीआई ने 28 जुलाई को विशेष अदालत में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अधिकारियों के मुताबिक, सोसायटी के एप से मिले रिकॉर्ड में उन छात्रों की बायोमेट्रिक एंट्री भी शामिल है, जो कुलकर्णी की ओर से अप्रैल में आयोजित विशेष कोचिंग कक्षाओं में आते थे। सीबीआई ने एप के रिकॉर्ड के जरिए छात्रों और उनके अभिभावकों की सोसाइटी में मौजूदगी की पुष्टि की। ये लोग नीट यूजी परीक्षा से कुछ दिन पहले अप्रैल में कुलकर्णी की सोसाइटी में आए थे। एजेंसी ने इन रिकॉर्ड को छात्रों के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन विश्लेषण से भी मिलाया। नीट यूजी परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी।

पूर्व जज यशवंत के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाओं के जरिए न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता का कहना था कि यशवंत वर्मा के इस्तीफा देने से उनके खिलाफ कथित अवैध नकदी रखने के मामले में आपराधिक कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती। उन्होंने अदालत को बताया कि इस बार उन्होंने पहले से शिकायत भी दर्ज कराई है। हालांकि, पीठ ने कहा कि पहले भी ऐसी याचिका खारिज हो चुकी है और यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अदालत ने टिप्पणी की कि यह केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास है। यशवंत वर्मा ने अप्रैल 2026 में अपने पद से इस्तीफा दिया था। उनके खिलाफ दिल्ली स्थित सरकारी आवास में मार्च 2025 में आग लगने के बाद बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी मिलने के आरोपों को लेकर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस्तीफे के बाद संसद में चल रही महाभियोग की कार्रवाई स्वतः समाप्त हो गई।

एक वापसी, कई सवालः क्या बांग्लादेश की राजनीति में फिर शुरू होगा नया संघर्ष

महेंद्र वेद

1971 में बांग्लादेश के गठन में मदद करने के बाद, ऐसा लगता है कि भारत को इसके उतार-चढ़ाव का हिस्सा बने रहना है। बांग्लादेश की बेदखल प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो भारत के प्रति खुलकर आभार जताने और उसकी दोस्ती को सबसे अधिक महत्व देने वाली नेता मानी जाती हैं, ने फिर कहा है कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह इस साल दिसंबर में अपना दूसरा निर्वासन खत्म कर स्वदेश लौटेंगी। वह वापस लौटने पर हिरासत में लिए जाने (उन्हें सजा और मौत का सामना करना पड़ सकता है) और 'यहां तक कि मारे जाने' के लिए भी तैयार हैं। सुरक्षा कारणों से गुप्त स्थान से मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'अपने लोगों के बीच लौटना मेरा फर्ज है।'

शायद इसी वजह से या किसी रणनीति के तहत, उन्होंने अपनी सार्वजनिक बातचीत केवल ऑडियो के माध्यम से की, वीडियो का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लगभग 30 मिनट तक अंग्रेजी में लिखित बयान पढ़ा, ताकि नई दिल्ली स्थित फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया में मौजूद विदेशी मीडिया तक अपनी बात पहुंचा सकें। उनकी जल्द होने वाली 'घर वापसी' से जुड़े इस राजनीतिक और भावुक कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा अमेरिका में रहने वाले उनके बेटे साजीब वाजेद जॉय का वीडियो संदेश भी था। उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए, जिनका जवाब शायद शेख हसीना खुद नहीं देना चाहती थीं। दोनों ने भारत का शुक्रिया अदा किया। जैसी कि अपेक्षा थी, ढाका ने इस घटनाक्रम पर नाराजगी जताई है, जबकि नई दिल्ली ने साफ कहा कि वह ऐसे किसी 'निजी' कार्यक्रम का समर्थन नहीं करता। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पड़ोसी देश प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों (जो पहले से ही तनावपूर्ण है और जिसे सुधारने की जरूरत है) को किस तरह संभालते हैं।

हसीना ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पुराने निर्वासन और वतन वापसी को याद किया। उनका पहला छह साल का निर्वासन दिल्ली में 1975 में शुरू हुआ था, जब उनके पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। मौजूदा निर्वासन के भी इस हफ्ते पांच अगस्त को दो साल पूरे हो गए। इस दौरान उन्होंने विरासत में

मिले उस धर्मनिरपेक्ष सपने और राजनीतिक ढांचे के नष्ट किए जाने का विरोध किया, जिसे उन्होंने मजबूत किया था। अब यह तो समय ही बताएगा कि वह इनमें से कुछ भी फिर से बहाल करेंगी या नहीं। हसीना ने बांग्लादेश में पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की 'वापसी' को लेकर चेतावनी दी। साथ ही, उन्होंने इस्लामी चरमपंथियों और अल-कायदा के बढ़ते प्रभाव की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि दुनिया को इस बारे में चिंता करनी चाहिए। लेकिन, दुनिया को इस्लामी चरमपंथ के बढ़ते असर और उससे भारत की सुरक्षा पर पड़ने वाले खतरे को लेकर कोई खास चिंता नहीं है। मजबूती से अपना बचाव करने के बावजूद, हसीना को भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और बांग्लादेश की 'विजेता ही हकदार' वाली हिंसक राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को लेकर कुछ सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। वह अपनी प्रतिद्वंद्वी बेगम खालिदा जिया का ही तरीका अपना रही थीं, जिन्होंने भी यही खेल खेला था। हालांकि, हसीना ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सत्ता से हटने के बाद हो रही उनकी आलोचना 'चुनिंदा' और एक सुनियोजित 'साजिश' का हिस्सा है। उनका कहना है कि इसमें इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया कि कैसे उन्होंने अपने देश को आर्थिक तरक्की और बेहतर मानव विकास संकेतकों की अभूतपूर्व राह पर आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने आलोचकों, खासकर अपने 'गैर-कानूनी' उत्तराधिकारी नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का नाम लेकर तीखा हमला किया। ढाका में अटकलें हैं कि यूनुस को अगला राष्ट्रपति चुना जा सकता है, क्योंकि मौजूदा राष्ट्रपति, जो हसीना के सहयोगी थे, को उनका कार्यकाल खत्म होने में दो साल बाकी रहते हुए ही हटा दिया गया था। यदि ऐसा होता है और तारिक रहमान भी इसके लिए सहमत होते हैं, तो यह फैसला हसीना की संभावित वापसी से पहले ही हो जाना चाहिए, ताकि राजनीतिक हालात और अधिक न उलझे। हसीना ने 2009 से 2024 तक के अपने 15 वर्ष के शासनकाल के दौरान हुई 'गलतियों' को भी माना। उन्होंने बताया कि कैसे नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के विवादित मुद्दे पर प्रदर्शनकारी छात्रों तक उनकी पहुंच की कोशिशें तब नाकाम हो गईं, जब 'अदृश्य ताकतों' के इशारे पर छात्रों ने मांगें बदल दीं। उन्होंने कहा, 'कानून-व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों पर सुनियोजित हमले किए गए। अधिकारियों की हत्या कर दी गई।

सुकमा खनन विवाद पर कांग्रेस का हमला

ग्रामीणों के साथ मैदान में उतरे विक्रम मंडावी

सुकमा। ग्राम पंचायत चिमलीपेंटा के तुमलपाड़ गांव में कथित अवैध खनन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। गुरुवार को बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हरीश कवासी ग्रामीणों से मिलने तुमलपाड़ पहुंचे।

दोनों नेताओं ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनीं और खनन कार्य को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नियमों की अनदेखी कर खनन जारी रहा तो कांग्रेस ग्रामीणों के साथ मिलकर जनआंदोलन करेगी।

बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के सामने आरोप लगाया कि कंपनी ने खनन शुरू करने से पहले हर परिवार को प्रतिवर्ष 25 हजार रुपये देने, स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, ऑटो उपलब्ध कराने और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने का आश्वासन दिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि खनन शुरू करने से पहले ग्रामसभा आयोजित नहीं की गई और उनकी सहमति के बिना ही उत्खनन शुरू कर दिया गया।

ग्राम पंचायत चिमलीपेंटा के सरपंच इरपा किस्टैया ने दावा किया कि पंचायत का प्रस्ताव अधिकारियों के दबाव में पारित कराया गया था। उन्होंने कहा कि गांव में ग्रामसभा नहीं हुई और फरवरी माह में कंपनी द्वारा किए गए रोजगार और विकास के वादे भी पूरे नहीं किए गए। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। उन्होंने प्रशासन से खनन कार्य बंद कराने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरीश कवासी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस क्षेत्र में आज भी स्कूल, आंगनबाड़ी और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वहां सड़क निर्माण के नाम पर खनन को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि अवैध खनन नहीं रोका गया तो कांग्रेस ग्रामीणों के साथ मिलकर चरणबद्ध आंदोलन करेगी।

बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि कांग्रेस विकास विरोधी नहीं है, बल्कि कानून के दायरे में विकास की पक्षधर है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना आवश्यक अनुमति और दस्तावेजों के खनन किया जा रहा है। प्रशासन शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि विकास की आड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अवैध दोहन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस ग्रामीणों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर जनआंदोलन शुरू करेगी।

गंदा पानी पीने को मजबूर हैं 35 बैगा परिवार

मौत हुई तो कौन जिम्मेदार?

कवर्धा। 15 अगस्त को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, जिसे भव्य बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से कुछ तस्वीर सामने आईं, जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। ग्राम पंचायत राजाढार के आश्रित गांव बेलापानी में बैगा जनजाति के करीब 35 परिवार बारिश में दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार मांग के बावजूद स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं मिल सका है। इतिहास

यह तस्वीरें कबीरधाम जिले के बेलापानी गांव की हैं, जहां बरसात के बीच नदी का मटमैला और दूषित पानी ही ग्रामीणों की प्यास बुझा रहा है। बैगा जनजाति के करीब 35 परिवारों के सामने पीने के साफ पानी का गंभीर संकट है। महिलाएं और बच्चे रोजाना इसी नदी से पानी भरकर घर लाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार गंदा पानी पीने से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। बाढ़ आने से पानी की और ज्यादा समस्या होती है।

ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और प्रशासन के अधिकारियों से हैंडपंप लगाने की मांग की। उन्होंने बताया कि वह उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा तक भी अपनी समस्या पहुंचा चुके हैं, लेकिन आज तक न हैंडपंप लगा और न ही कोई स्थायी पेयजल व्यवस्था की गई।

बेलापानी के ग्रामीणों ने कहा कि दूषित पानी पीने से किसी ग्रामीण की जान जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने मांग की है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि तत्काल हैंडपंप और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था चाहिए। समय रहते पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई तो स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं बढ़ सकती हैं।

सड़कों पर लालटेन लेकर प्रदर्शन:यूथ कांग्रेस ने महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर के खिलाफ घेरा बिजली विभाग

धमतरी। प्रदेशभर में स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। धमतरी में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में बढ़ोतरी का आरोप लगाते हुए यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरी। लालटेन के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली विभाग का घेराव किया। राजनीति

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जनता को राहत देते हुए 400 यूनिट तक बिजली माफ की थी। लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार ने उसे घटाकर आधी यानी सिर्फ 200 यूनिट कर दिया है। यह जनता के साथ धोखा है। इसी के विरोध में आज बिजली विभाग का घेराव किया गया है।

मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई थी। इधर बिजली विभाग के अधिकारियों ने पूरे मामले को शासन स्तर का बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। अधिकारियों का कहना है कि दरें और यूनिट माफी का फैसला शासन स्तर से होता है। फिलहाल यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिलों पर फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा

अवैध संबंध में पत्नि ने कर दी पति की हत्या

बैकुंठपुर। कोरिया जिले से हत्या का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने पति को चरित्र शंका के चलते मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरु कर दी है।

यह पूरा मामला चरचा थाना अंतर्गत ग्राम तिलवन डांड के पिपरपारा का है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला बबली को शक था कि उसके पति जयवीर का अवैध संबंध पड़ोस की विधवा महिला के साथ चल रहा है। इसको लेकर अक्सर दोनों के बीच विवाद भी होता था। 6 अगस्त को बबली राशन दुकान से घर लौट रही थी, तभी उसको शक हुआ कि उसका पति विधवा महिला के साथ है और उसने महिला के घर में घुसकर तलाशी ली। इस दौरान जयवीर अंदर छिपा मिला। इसके बाद बबली आग बबूला हो गई और दोनों के बीच जमकर झूमा झटकी हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बबली ने जयवीर को धक्का दे दिया। मुंह के बल पत्थर पर गिरने से वह बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे पड़ोसियों की मदद से घर ले जाया गया और फिर कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बबली को हिरासत में लिया और चरचा थाने में मामला दर्ज किया गया। मौत चोंट लगने से हुई या फिर कोई और वजह थी इसका खुलासा फोरेंसिक जांच के बाद ही होगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

भाई बहन की जान लेने वाले भालू की मौत

रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने किया था हमला

कांकेर। कांकेर में रेस्क्यू किए गए भालू और तेंदुआ की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि इनमें से भालू की रायपुर और कांकेर के कोटलभट्टी में इलाज के दौरान मौत हुई। दोनों जानवरों का रेस्क्यू वन विभाग ने किया था।

आपको बता दें कि कांकेर जिले के लारगांव मरकाटोला में 5 अगस्त को भालू का आतंक देखने को मिला था। भालू ने इस गांव में 3 लोगों पर हमला किया था इस हमले में भाई बहन की मौत हुई थी।

जबकि हमले में एक बहन बुरी तरह से घायल है जिसका इलाज रायपुर में चल रहा है। भालू हमले के दौरान इतना आक्रामक हो चुका था कि भाई बहन की मौत के बाद भी उनके शव से दूर जाने के बजाय उन्हें नोंच रहा था। इसके बाद जब वनविभाग मौके पर पहुंचा और भालू को ट्रैक्यूलाइज किया तो आक्रोशित ग्रामीणों ने बेहोश भालू पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से हुए इस हमले में भालू बुरी तरह से जख्मी हो गया। भालू को जख्मी हालत में वन विभाग की टीम अपने साथ लेकर चली गई। लेकिन इलाज के दौरान भालू ने दम तोड़ दिया।

एक दिन पहले भोजन पानी की तलाश में भटकते हुए एक तेंदुआ कोटलभट्टी पहुंचा था। इस दौरान एक ग्रामीण की बाड़ी में बने कुएं में तेंदुआ दिर गया।सुबह जब लोगों को इसकी खबर लगी तो वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। विभाग के पहुंचते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन तेंदुआ को कुंए में से शाम को बाहर निकाला जा सका। विभाग ने कोटलभट्टी में ही तेंदुआ का इलाज शुरु किया,लेकिन रात में तेंदुआ ने दम तोड़ दिया।भालू को रेस्क्यू कर बाद रायपुर जंगल सफारी ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है, जिसकी जांच जारी है। वहीं कुआं में गिरे तेंदुआ की रेस्क्यू के बाद मौत हो गई है, अनुमान लगाया जा रहा है कि अधिक पानी पीने के कारण मौत हुई होगी, जांच की जा रही है-रौनक गोयल,डीएफओ कांकेर

इस तरह दो अलग-अलग इलाके से रेस्क्यू किए गए भालू और तेंदुए की मौत हो गई है। दो जीवों की मौत ने वन विभाग की सुरक्षा उपायों को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि एक ओर जहां भालू पर भीड़ ने हमला किया वहीं दूसरी ओर तेंदुआ को कुएं से निकालने में काफी ज्यादा वक्त लगा।ऐसे में चाहिए कि वन्य जीवों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बरती जाए।

मक्के की खड़ी फसल पर चला दिया ट्रैक्टर

जगदलपुर। बस्तर ब्लॉक के कुमली पंचायत में वन भूमि पर खेती को लेकर वन विभाग और किसानों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। वन विभाग ने करीब 6 हेक्टेयर यानी 15 एकड़ वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई की है। आरोप है कि चार लोगों ने वन भूमि पर कब्जा कर मक्के की फसल लगाई थी।

सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर चलवाकर खड़ी मक्के की फसल को नष्ट कर दिया। विभाग का कहना है कि कार्रवाई अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की गई है और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ किसान इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। किसानों का दावा है कि इस इलाके में करीब 100 किसान लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं। किसान हेमलाल पांडे के मुताबिक, पंचायत की बैठक में खड़ी फसल के लिए तीन महीने की मोहलत देने का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इसके बावजूद खेतों में लगी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया गया, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है।

किसानों का कहना है कि अगर अतिक्रमण है तो कार्रवाई सभी के पुराने रिकॉर्ड और जमीन की स्थिति की जांच के आधार पर होनी चाहिए। वहीं वन विभाग का कहना है कि फिलहाल मिली सूचना के आधार पर चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और पूरे मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता में 78 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा

दंतेवाड़ा। जिले के किरंदुल पुलिस एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, किरंदुल के संयुक्त तत्वावधान में विद्यार्थियों के बीच नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में कुल 78 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में नशा मुक्ति विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में 38 विद्यार्थियों तथा यातायात जागरूकता एवं सुरक्षा विषय पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में 40 विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। निबंध प्रतियोगिता में उच्चमा वर्ग में कु. शशिकला - प्रथम स्थान, माध्यमिक वर्ग में रवि कड़ती प्रथम स्थान, चित्रकला प्रतियोगिता में उमा वर्ग में कु. कावेरी प्रथम स्थान, माध्यमिक वर्ग में मुकेश बारसे प्रथम स्थान कार्यक्रम के समापन पर विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, सभी प्रतिभागियों को सुरक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनने तथा नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा का संदेश समाज तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया।

हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

नारायणपुर। जिले के थाना कुकड़ाझोर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी राजकुमार कावड़े को गिरफ्तार कर पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना करना स्वीकार किया तथा उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार टंगिया बरामद की गई है। थाना कुकड़ाझोर में कार्यवाही उपरांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना कुकड़ाझोर में अपराध क्रमांक 03/2026 के तहत धारा 296, 351(2), 115(2), 333 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रार्थी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार 02 अगस्त 2026 की शाम गांव में आयोजित बैठक के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी राजकुमार कावड़े ने पहले प्रार्थी के साथ गाली-गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी। कुछ समय बाद आरोपी प्रार्थी के घर पहुंचा और टंगिया से उसके सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

शासकीय भूमि में हेरफेर के आरोप का सौंपा ज्ञापन

जगदलपुर। बस्तर जिले के ग्राम पंचायत तुरपुरा के आश्रित ग्राम पल्लीभाटा में ग्राम कोटवार पर शासकीय भूमि में हेरफेर एवंशासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही के गंभीर आरोप को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एकजुट होकर एसडीएम को हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में आरोप लगाया कि ग्राम कोटवार पिलाराम कोर्राम द्वारा शासकीय भूमि से जुड़े मामलों में अनियमितताएं की गई हैं तथा अपने शासकीय दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की विस्तृत एवं निष्पक्ष जांच कर दोष सिद्ध होने की स्थिति में उन्हें पद से हटाने और नए कोटवार की नियुक्ति करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होने से गांव में शासकीय भूमि से जुड़े कथित हेरफेर की वास्तविक स्थिति सामने आएगी और भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लग सकेगी। उन्होंने दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की भी मांग की।

जीरम घाटी नक्सली हमला: 10 अगस्त को होगी अंतिम बहस

जगदलपुर। बहुचर्चित जीरम घाटी नक्सली हमले से जुड़े मामले की सुनवाई अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। लंबे समय से न्यायालय में चल रहे इस प्रकरण में आगामी 10 अगस्त को अंतिम बहस निर्धारित की है। इसके बाद न्यायालय निर्णय की तिथि घोषित कर सकता है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन चल रहा है। इनमें से एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है, जबकि शेष आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में सुनवाई जारी है। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कुल 101 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए हैं। गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अब मामला अंतिम बहस के चरण में पहुंचा है। 10 अगस्त को होने वाली अंतिम बहस के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष अपने-अपने अंतिम तर्क न्यायालय के समक्ष रखेंगे। इसके बाद सभी की नजरें न्यायालय के फैसले पर टिकी रहेंगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय कितने आरोपियों को दोषी ठहराता है।

गेंदे की खेती से कुमारी चंद्राकर ने बढ़ाई अपनी आमदनी

महासमुंद। जिले के बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम भदरसी की कृषक श्रीमती कुमारी चंद्राकर पति श्री दाऊलाल चंद्राकर ने पारंपरिक खेती के साथ उद्यानिकी फसलों को अपनाकर अपनी कृषि आय में वृद्धि की है। श्रीमती चंद्राकर बताती हैं कि धान की खेती में अधिक लागत और अपेक्षाकृत कम उत्पादन के कारण उनका रुझान धीरे-धीरे उद्यानिकी फसलों की ओर बढ़ा। इसके बाद उन्होंने सब्जियों और फूलों की खेती को अपनी नियमित कृषि गतिविधियों का हिस्सा बनाया। वर्तमान में वे धनिया, प्याज, बैंगन, मूली, भाजी सहित विभिन्न उद्यानिकी फसलों की खेती कर रही हैं। वर्ष 2025-26 में श्रीमती कुमारी चंद्राकर ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत पुष्प क्षेत्र विस्तार घटक के तहत गेंदा फूल की खेती की। उनके पास कुल 0.64 हेक्टेयर सिंचित कृषि भूमि है, जिसमें उन्होंने गेंदा की फसल लगाई। शासन की योजना से उन्हें 0.64 हेक्टेयर क्षेत्र में गेंदा फसल के लिए 12,800 रुपये का अनुदान डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हुआ।

तबादले के आधार पर वरिष्ठता समाप्त नहीं की जा सकती : हाईकोर्ट

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल प्रशासनिक कारणों से किए गए तबादले के आधार पर किसी कर्मचारी की अर्जित वरिष्ठता समाप्त नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने वन विभाग के 31 जुलाई 2014 के सर्कुलर की उस शर्त को सीमित सीमा तक असंवैधानिक करार दिया है, जिसके तहत एक वन वृत्त से दूसरे वन वृत्त में स्थानांतरित कर्मचारियों को संबंधित वृत्त की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाता था।

मामले में वर्ष 2013 में प्रत्यक्ष भर्ती से नियुक्त कई वनरक्षकों ने याचिका दायर कर कहा था कि उनका स्थानांतरण केवल प्रशासनिक कारणों से हुआ था, फिर भी भर्ती में प्राप्त मेरिट को नजर अंदाज कर उन्हें वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा गया। उनका तर्क था कि वैधानिक भर्ती नियमों के विपरीत केवल एक कार्यपालिक सर्कुलर के आधार पर उनकी वरिष्ठता कम कर दी गई, जिससे पदोन्नति के अवसर प्रभावित हुए।

इधर राज्य शासन ने दलील दी कि 31 जुलाई 2014 के सर्कुलर तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के तहत अंतरवृत्त स्थानांतरण होने पर कर्मचारी की वरिष्ठता स्थानांतरण वाले वृत्त में सबसे नीचे निर्धारित की जाती है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन सही ढंग से निरस्त किए गए।

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता स्थानांतरण के जरिए नियुक्त कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि उनकी नियुक्ति प्रत्यक्ष भर्ती से हुई थी और बाद में प्रशासनिक कारणों से उनका तबादला किया गया। ऐसे में स्थानांतरण को दंड का आधार बनाकर उनकी भर्ती मेरिट समाप्त नहीं की जा सकती। अदालत ने साफ किया कि प्रशासनिक तबादला सेवा की सामान्य प्रक्रिया है और इससे कर्मचारी को प्रतिकूल नागरिक परिणाम नहीं भुगतने पड़ सकते, जब तक किसी वैधानिक प्रावधान में इसका स्पष्ट प्रावधान न हो।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 31 जुलाई 2014 के सर्कुलर की संबंधित शर्त को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के विपरीत बताते हुए सीमित सीमा तक निरस्त कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन खारिज करने वाले 25 सितंबर 2025 के आदेश रद्द कर राज्य शासन को निर्देश दिया कि उनकी वरिष्ठता भर्ती की मूल मेरिट और लागू वैधानिक नियमों के आधार पर 90 दिनों के भीतर पुनर्निर्धारित की जाए।

पशुपालकों को सस्ती दर पर मिलेंगी जेनेरिक पशु औषधियां

धमतरी। पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित अंतर्गत पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती पशु औषधियां उपलब्ध कराने की दिशा में जिले में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी क्रम में पशु औषधि विक्रय केंद्र की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदन के दस्तावेजों का सत्यापन पूर्ण कर लिया गया है। संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में विकासखंड धमतरी से प्राप्त आवेदन पोर्टल पर स्वीकृत होने के पश्चात आवेदन की अर्हता पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन 6 अगस्त 2026 को उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला धमतरी द्वारा किया गया। इस दौरान आवेदक श्री देवेश कुमार सिन्हा, सिन्हा कृषि केंद्र (पीएम किसान समृद्धि केंद्र), ग्राम कोलियरी, विकासखंड धमतरी तथा फार्मासिस्ट श्री प्रतीक वाटवानी, धमतरी उपस्थित रहे। पशुपालकों को सस्ती दर पर मिलेंगी जेनेरिक पशु औषधियां उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक पोर्टल पर स्वीकृत आवेदनों में दस्तावेज सत्यापन के चरण तक पहुंचने वाला यह एकमात्र आवेदन है, जिससे जिले को इस पहल में अग्रणी अवसर मिला है। क्लस्टर का संचालन प्रारंभ होने के बाद विकासखंड धमतरी क्षेत्र के पशुपालकों को जेनेरिक पशु औषधियां सस्ती एवं उचित दरों पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी। इससे पशुओं के उपचार में होने वाले खर्च को कम करने, समय पर दवाइयां उपलब्ध कराने तथा पशुधन के स्वास्थ्य संरक्षण में मदद मिलेगी। साथ ही पशुपालकों को आवश्यक पशु चिकित्सा सेवाओं और औषधियों के लिए दूरस्थ क्षेत्रों की ओर जाने की आवश्यकता कम होगी 7 कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने कहा कि जिले में पशुपालकों को बेहतर एवं सुलभ पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। पशु औषधि विक्रय केंद्र प्रारंभ होने से पशुपालकों को आवश्यक जेनेरिक पशु औषधियां उचित एवं सस्ती दरों पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। इससे समय पर उपचार की सुविधा मिलने के साथ पशुपालकों के उपचार संबंधी खर्च में भी कमी आएगी।

संक्षिप्त समाचार

रायपुर नगर निगम में अभियंताओं को दी गयी नवीन पदस्थापना

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री संबित मिश्रा ने प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर नगर पालिक निगम में अभियंताओं को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक नवीन पदस्थापना देने से सम्बंधित आदेश जारी किए हैं। जारी प्रशासनिक आदेश के अनुसार नगर निगम रायपुर में सहायक अभियंता कु. रश्मि भौमना जोन 1 से जोन 4, सहायक अभियंता श्री गुलाबचन्द्र कर्ष जोन 4 से जोन 9, प्रभारी सहायक अभियंता श्री आशीष श्रीवास्तव जोन 6 से जोन 10, सहायक अभियंता कु. रेणुका खूंटे जोन 9 से जोन 3, प्रभारी सहायक अभियंता श्री फराज फारुकी जोन 10 से जोन 2, सहायक अभियंता सुश्री जिज्ञासा जैन जोन 9 से जोन 7, सहायक अभियंता श्री मनोज साहू जोन 10 से जोन 9, श्री अबरार खान उपअभियंता जोन 8 से जोन 2, उपअभियंता श्री जयनन्दन डहरिया जोन 3 से जोन 2, उपअभियंता श्री अंकुर मिश्रा जोन 8 से जोन 4, उपअभियंता श्री सुधीर भट्ट जोन 2 से जोन 5,उपअभियंता श्रीमती अंकिता जनार्दन जोन 9 से जोन 5, उपअभियंता श्री निर्मल तिग्गा जोन 5 से जोन 6, उपअभियंता श्री कृष्ण कुमार साहू जोन 9 से जोन 6, श्रीमती अंकिता अग्रवाल जोन 4 से जोन 8, श्रीमती मनीषा निराला जोन 5 से जोन 8,उपअभियंता श्रीमती विद्या देशलहरा जोन 6 से जोन 9, उपअभियंता श्री सोहन गुप्ता मुख्यालय से जोन 9, उपअभियंता श्री अमित सरकार मुख्यालय से जोन 10 पदस्थ किये गए है।

बेबीलान टावर प्रबंधन पर निगम ने सड़क किनारे मलबा फेंकने पर लगाया जुर्माना

रायपुर। वीआईपी रोड स्थित बेबीलान टावर के पास मुख्य सड़क किनारे मलबा फेंकने की शिकायत पर रायपुर नगर निगम के जोन 9 के स्वास्थ्य अधिकारी बैरोन बंजारे, उमेश नामदेव और स्वच्छता निरीक्षक भोला तिवारी ने औचक निरीक्षण किया और शिकायत सही मिलने पर कारोबारी जसवीर सिंह खनूजा पर 25 हजार रुपए का ई-जुर्माना लगाया। साथ ही भविष्य में दोबारा ऐसी लापरवाही नहीं करने की सख्त चेतावनी भी दिया। नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य सड़क किनारे एक व्यावसायिक परिसर की ओर से बड़ी मात्रा में निर्माण मलबा फेंके जाने की शिकायत नगर निगम को मिली थी। शिकायत मिलते ही नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद जोन-9 के जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में जोन-9 के स्वास्थ्य अधिकारी बैरोन बंजारे, उमेश नामदेव और स्वच्छता निरीक्षक भोला तिवारी ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि वीआईपी रोड किनारे स्थित बेबीलान टावर प्रबंधन की ओर से बड़ी मात्रा में निर्माण मलबा फेंका गया था। इससे आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी और सड़क की स्वच्छता भी खराब हो रही थी।

मैक में इंटीरियर डिजाइन विभाग ने मनाया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

रायपुर। महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज,

रायपुर के इंटीरियर डिजाइन विभाग द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर टाई एंड डाई कार्यशाला का आयोजन महाविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत की समृध्द हस्तकरघा परंपरा, पारंपरिक वस्त्र कला एवं प्राकृतिक रंगाई तकनीकों से परिचित कराना तथा उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना था। कार्यशाला में इंटीरियर डिजाइन एवं फैषन डिजाइन विभाग के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए टाई एंड डाई तकनीक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के आकर्षक डिजाइन तैयार किए। विद्यार्थियों को कपड़ों पर पारंपरिक एवं आधुनिक डिजाइनों की रंगाई, रंगों के संयोजन, फोल्डिंग तकनीक तथा डिजाइन निर्माण की व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान हस्तनिर्मित वस्त्रों के महत्व, भारतीय हथकरघा उद्योग की समृद्ध विरासत तथा पर्यावरण-अनुकूल वस्त्र निर्माण की उपयोगिता पर भी विस्तार से चर्चा की गई। यह कार्यशाला उनके कोर्स करिकुलम का भाग है जिसमें उन्होंने अपने नवाचार एवं कलात्मक प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस कार्यशाला ने उन्हें पारंपरिक भारतीय कला एवं संस्कृति को आधुनिक डिजाइन अवधारणाओं से जोड़ने का अवसर प्रदान किया गया साथ ही स्वरोजगार एवं उद्यमिता के प्रति भी रुचि विकसित हुई।

नांदघाट-मुंगेली रोड होगा फोरलेन, राज्य शासन ने मंजूर किए 21.81 करोड़

रायपुर। राज्य शासन ने बेमेतरा जिले के नांदघाट से मुंगेली जिला मुख्यालय तक टू-लेन सड़क के फोरलेन में उन्नयन के लिए 21 करोड़ 81 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से 36.40 किमी फोरलेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने मंत्रालय से राशि स्वीकृति के संबंध में प्रमुख अभियंता को परिपत्र जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों एवं संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने प्रमुख अभियंता को कार्य की निविदा समय-सीमा में करने, निर्माण कार्य प्राक्कलन व कार्य संपादित करने में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने निर्माण एजेंसी से अनुबंधित समय-सीमा में काम पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कराने को कहा है।

कांग्रेस करती है नैरेटिव की राजनीति, एक जेब में पेट्रोल तो दूसरे में है माचिस : जायसवाल

बिलासपुर। बिलासपुर दौरे पर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी।स्वास्थ्य मंत्री ने अटैचमेंट व्यवस्था, झोलाछाप डॉक्टर, हरिओम अस्पताल विवाद, सर्पदंश मुआवजा, मल्टीसुपर स्पेशलिटी अस्पताल और कोटा क्षेत्र में बढ़ते मलेरिया को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर अपना पक्ष रखा।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जरूरत के अनुसार कर्मचारियों का अटैचमेंट किया जाता है। फिलहाल अटैचमेंट समाप्त किए जा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फिर से किए जा सकते हैं। वहीं झोलाछाप डॉक्टरों के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस या

नियमों के विरुद्ध काम करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। शिकायत मिलने पर जांच भी कराई जाएगी। श्यामबिहारी जायसवाल के बयान पर कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री को फर्जी लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए। जो बिना डिग्री, नालेज के लोगों का इलाज कर रहे, तो यह घातक है। ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों का इलाज के दौरान मौत न हो।

हरिओम अस्पताल में महिला के शव को रोके जाने के मामले में श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इसे बेवजह तूल दिया गया और प्रदेश में किसी गरीब का शव पैसों के अभाव में नहीं रोका जाता। सर्पदंश मुआवजा मामले पर उन्होंने कहा कि विधानसभा में मामला उठने के बाद व्यापक जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी।

मंत्री ने कहा कांग्रेस के लोग केवल नैरेटिव सेट करते हैं। केवल नैरेटिव के आधार पर पॉलिटिक्स करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नही है। केवल बिजली बिल के मुद्दे को लेकर प्रदेश के लोगों को भड़काकर गलत तरीके से उसको प्रदर्शित करके लोगों को गुमराह करने का का कांग्रेस वाले काम कर रहे हैं।

श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा मैंने जो पेट्रोल वाला जो बयान दिया था कांग्रेस के संगठन संदर्भ में मीडिया वालों ने पूछा था तो मैंने बताया कि कांग्रेस एकजुट होकर कभी नहीं चलते हैं। पंजाब में आप लोगों ने देख लिया कि वहां प्रभारी के रूप में भूपेश बघेल जी हैं उनके खिलाफ नारे लगाये जा रहे हैं। जो नया नही है कांग्रेस के ये नेता कभी एक नही हो सकते उनके एक पॉकेट में पेट्रोल दूसरे पॉकेट में माचिस लेकर चलते हैं।

बिलासपुर का शुभ मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पीपीपी मॉडल पर संचालित होगा, जहां आम और गरीब मरीजों को सिम्स और जिला अस्पताल की तरह निशुल्क उपचार मिलेगा। बस्तर और कोटा में बढ़ते मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर सर्वे कर रोकथाम और उपचार का अभियान चला रही हैं।जिस तरह से प्रदेश में नक्सलवाद का सफाया हुआ है,वैसे ही मलेरिया का भी अंत होगा।

दिव्यांग बालिका विकास गृह के अतिरिक्त कमरों का शिलान्यास आज

■ **विधायक राजेश मूणत मुख्य अतिथि और महापौर मीनल छगन चौबे होंगी विशेष अतिथि**

रायपुर। समता कॉलोनी स्थित महाराष्ट्र मंडल के दिव्यांग बालिका विकास गृह में 20 लाख रुपये की विधायक निधि से नगर पालिक निगम की ओर से बनने वाले अतिरिक्त कमरों का शिलान्यास समारोह शनिवार को दोपहर 11 बजे आयोजित किया गया है। समारोह के मुख्य अतिथि रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश मूणत और विशेष अतिथि महापौर मीनल छगन चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर, जोन- सात की अध्यक्ष श्वेता विश्वकर्मा, पीडब्ल्यूडी प्रभारी दीपक जायसवाल, एमआईसी सदस्य भोलाराम साहू, पार्षद आनंद अग्रवाल, भाजपा के तात्यापारा के मंडल अध्यक्ष चैतन्य टावरी, भाजपा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के संयोजक ओंकार बैस और पार्षद मीना ठाकुर कार्यक्रम के विशेष अतिथि होंगे। महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। पीडब्ल्यूडी प्रभारी दीपक जायसवाल ने बताया कि दिव्यांग बालिका विकास गृह में अतिरिक्त कमरों के शिलान्यास के अलावा भी समारोह में प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 500 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। साथ ही उज्जवला योजना के 30 आवेदनकर्ताओं को इस मौके पर ससम्मान गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। जायसवाल के अनुसार इस मौके पर चिरहुलडीह वार्ड में दो स्थानों रामकुंड और कारी तालाब आमापारा सब्जी बाजार के पास लगे हाईमास्ट का भी लोकार्पण अतिथिगण करेंगे।

संस्कृति मंत्री ने दिया स्वदेशी अपनाने का संदेश

■ **राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकरों के सम्मान और श्वोकल फॉर लोकलश् अभियान को मजबूत बनाने की अपील**

रायपुर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने प्रदेशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने तथा हथकरघा से निर्मित वस्तुओं के अधिकाधिक उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का उल्लेख करते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्पकला और लाखों बुनकर परिवारों के सम्मान से जुड़ा जन आंदोलन है।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के कुशल बुनकरों द्वारा निर्मित पारंपरिक गमछा धारण कर प्रदेश की समृद्ध हस्तकरघा परंपरा को सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि यह गमछा

केवल एक परिधान नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान, श्रम, परंपरा और स्थानीय शिल्प कौशल का जीवंत प्रतीक है।

श्री अग्रवाल ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी और हथकरघा उत्पादों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि जब हम स्थानीय बुनकरों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का उपयोग करते हैं, तब हम न केवल उनकी आजीविका को सशक्त बनाते हैं, बल्कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक नागरिक का यह छोटा-सा प्रयास आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में बड़ा योगदान सिद्ध होगा।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बुनकर अपनी पारंपरिक कला, उत्कृष्ट शिल्पकौशल और रचनात्मकता के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिला रहे हैं। ऐसे प्रतिभाशाली शिल्पकारों का उत्साहवर्धन करना हम सबका सामूहिक दायित्व है।

श्री अग्रवाल ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर नागरिकों से अपने पसंदीदा हथकरघा उत्पाद के साथ वीडियो अथवा चित्र साझा करने और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अभियान से जुड़ने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस जनभागीदारी से देश-दुनिया तक हमारे बुनकरों की अद्भुत कला, उनकी मेहनत और भारतीय हथकरघा की समृद्ध परंपरा को नई पहचान मिलेगी।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेशवासी स्वदेशी अपनाने के इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए श्वोकल फॉर लोकलश् के संकल्प को और अधिक सशक्त बनाएंगे तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

राइस मिलर्स की खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक

रायपुर। मंत्रालय, महानदी भवन में खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक हुई, इस दौरान राइस मिल के कस्टम मिलिंग में आ रही समस्याओं एवं सुझाव पर चर्चा की गई।

छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल बोथरा ने बताया कि बैठक में वर्ष 2026-27 की कस्टम मिलिंग नीति एवं चावल जमा व्यवस्था सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। जिसमें इस वर्ष 10 प्रतिशत इम्प्रूव राइस नान में जमा किया जाएगा, स्टेट पूल के अंतर्गत लगभग 17.32 लाख टन चावल जमा होगा, सेंट्रल पूल से लगभग 16.00 लाख टन चावल नान में जमा किया जाएगा, लगभग 10.00 लाख टन बॉयल्ड (उसना) राइस 5 प्रतिशत एफसीआई में जमा किया जाएगा, लगभग 5.00 लाख टन (10 प्रतिशत)अरवा चावल एफसीआई में जमा

होगा, शेष लगभग 25 प्रतिशत ब्रोकन अरवा चावल एफसीआई में जमा किया जाएगा।

बोथरा ने बताया कि राइस मिल परिसर में निर्मित गोदाम एवं वर्तमान राइस मिलों में तकनीकी उन्नयन पर भी सब्सिडी दी जाए। बैठक के दौरान राइस मिलर्स की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों पर भी गंभीरता से चर्चा हुई। एसोसिएशन ने 10 प्रतिशत इंप्रूव राइस को लेकर अपनी चिंता वयक्त की और विशेष रूप से प्रोत्साहन राशि में वृद्धि, भंडारण (स्टोरेज) शुल्क, सूखत का प्रावधान, पूरे जमा बारदाना पर उपयोगिता शुल्क, 30 नंबर 2026 की स्थिति पर बकाया चावल को नान में ट्रांसफर करने सकारात्मक विचार-विमर्श हुआ।

निगम आयुक्त ने 5 पंजीकृत इंजीनियर को किया ब्लैकलिस्ट

रायपुर। नगर पालिक निगम, रायपुर में भवन अनुज्ञा (बिल्डिंग परमिशन) प्रक्रिया को पूर्णत: पारदर्शी, समयबद्ध एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में आयुक्त श्री संबित मिश्रा द्वारा सख्त प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 5 पंजीकृत इंजीनियरों को 1 वर्ष की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट (निलंबित) किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

भवन अनुज्ञा प्रकरणों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि संबंधित पंजीकृत इंजीनियरों द्वारा बीपीएमएस (बिल्डिंग परमिशन मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर प्रस्तुत प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेजों की कमी एवं बार-बार तकनीकी त्रुटियां की गईं, जिसके कारण आवेदन लगातार रीएससाइन होते रहे तथा भवन अनुज्ञा प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में नहीं हो सका। इन अनियमितताओं के संबंध में सभी संबंधित इंजीनियरों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरणों का परीक्षण करने पर वे संतोषजनक नहीं पाए गए, जबकि एक प्रकरण में निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त तथ्यों के परीक्षण के उपरांत आयुक्त श्री संबित मिश्रा द्वारा भवन अनुज्ञा प्रक्रिया की पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता बनाए रखने तथा भविष्य में ऐसी लापरवाही की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से 5 पंजीकृत इंजीनियरों को 1 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट करने के आदेश जारी किए गए है. ब्लैकलिस्ट अवधि के दौरान उक्त सम्बंधित 5 पंजीकृत इंजीनियर नगर पालिक निगम रायपुर के बीपीएमएस पोर्टल के माध्यम से किसी भी प्रकार के भवन अनुज्ञा आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे तथा उनके नाम से कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री संबित मिश्रा ने कहा कि नगर पालिक निगम रायपुर में भवन अनुज्ञा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही, दस्तावेजों की कमी, तकनीकी त्रुटि अथवा नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। नागरिकों को समयबद्ध एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना नगर पालिक निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा जीपीएम

■ **18 से 21 अगस्त तक जुटेंगे प्रदेशभर के खिलाड़ी**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में खेल संस्कृति को नई गति मिल रही है। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार लगातार प्रभावी पहल कर रही है। इसी कड़ी में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला 18 से 21 अगस्त तक आयोजित होने वाली 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। चार दिवसीय इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में प्रदेश के पांचों संभागों से 14 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 540 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे।

राज्य सरकार खेलों को केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और स्वस्थ जीवन शैली का सशक्त आधार मानती है। शालेय स्तर पर आयोजित होने वाली ऐसी प्रतियोगिताएं युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने के साथ-साथ बड़े मंचों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करती हैं।

प्रतियोगिता के दौरान जिम्नास्टिक

(बालक एवं बालिका), क्रिकेट (बालक), ताईक्वांडो (बालक एवं बालिका) तथा कबड्डी (बालिका) की स्पर्धाएं आयोजित होंगी। प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी पांचों संभागों के खिलाड़ी, प्रशिक्षक एवं अधिकारी सहभागिता करेंगे। आयोजन से खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा की भावना, टीम भावना और खेल उत्कृष्टता को नई दिशा मिलेगी।

प्रतियोगिता के सफल एवं गरिमामय आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेकर तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समय-सीमा में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि राज्यभर से आने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अधिकारियों को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

बैठक में खेल स्थलों के चयन, खिलाड़ियों के आवास एवं भोजन, परिवहन, स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा सुविधा, पेयजल, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन तथा उद्घाटन एवं समापन समारोह की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को सौंपे गए दायित्वों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकेश रावटे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी श्री रजनीश तिवारी सहित खेल एवं युवा कल्याण, वन, स्वास्थ्य, आदिवासी विकास, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विद्युत, खाद्य, परिवहन तथा नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। यह प्रतियोगिता न केवल प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी, बल्कि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को राज्य के प्रमुख खेल आयोजनों के सफल मेजबान के रूप में नई पहचान भी दिलाएगी।

सुप्रीम कोर्ट से भूपेश बघेल को लगा झटका

भाजपा नेता विजय बघेल द्वारा लगाई गई चुनाव याचिका पर अब होगी सुनवाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भूपेश बघेल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बघेल चुनाव याचिका के ट्रायल के दौरान अपने सभी कानूनी और तथ्यात्मक आपत्तियां उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने बघेल की ओर से दायर चुनौती पर सुनवाई की। चुनाव याचिका भाजपा नेता एवं बघेल के चुनावी प्रतिद्वंद्वी विजय बघेल ने लगाया है।

चुनाव याचिका में आरोप लगाया

गया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मतदान से 48 घंटे पहले लागू साइलेंस पीरियड के दौरान भूपेश बघेल ने रोड शो किया, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन है। बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आरोप सही मान भी लिया जाए तो यह केवल धारा 126 के तहत चुनाव संबंधी अपराध हो सकता है, लेकिन इसे धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता।

सिब्बल ने कहा, धारा 126 एक चुनावी अपराध है। यह भ्रष्ट आचरण नहीं है। भ्रष्ट आचरण धारा 123 के तहत आता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कथित घटना का चुनाव परिणाम पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि भूपेश बघेल ने लगभग 20 हजार मतों के अंतर से चुनाव जीता था। उन्होंने कहा कि कथित रोड शो में करीब 200 लोग थे और बघेल उस समय मुख्यमंत्री थे तथा उन्हें जेड+ सुरक्षा प्राप्त थी।

हालांकि, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि कथित उल्लंघन से चुनाव परिणाम वास्तव में प्रभावित हुआ या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है, जिसका निर्धारण साक्ष्यों के आधार पर किया जाना आवश्यक है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि जब आरोप भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में ही नहीं आता तो बघेल को पूरी चुनावी सुनवाई से गुजरने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। इस पर न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की कि आपके पास बचाव के लिए एक तर्कसंगत मामला है।

सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए बघेल की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें यह स्वतंत्रता दी कि वे चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान अपने सभी कानूनी और तथ्यात्मक तर्क हाईकोर्ट के समक्ष उठा सकते हैं। मामला 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पाटन विधानसभा सीट से भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका से जुड़ा है। भाजपा नेता विजय बघेल ने आरोप लगाया है कि मतदान से एक दिन पहले, 16 नवंबर 2023 को भूपेश बघेल ने रोड शो किया, जो धारा 126 के तहत लागू 48 घंटे के मौन काल का उल्लंघन है।

कार्यालय जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नगर सेना उत्तर बस्तर कांकेर

// नीलामी विज्ञापन //

क्रमांक /946/भण्डार/2026 कांकेर दिनांक 28/07/2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस विभाग के अन्तर्गत जिला कांकेर के निष्प्रयोज्य घोषित भण्डार सामग्रियों की नीलामी दिनांक 10.08.2026 दिन सोमवार को 11.00 बजे किया जाना है। कार्यालयीन समय में सिंगारभाट स्थित होमगार्ड कार्यालय कैम्प परिसर में कि जावेगी। निष्प्रयोज्य घोषित सामग्रियों में होमगार्ड जवानों की वर्दी सामग्री जैसे पेन्ट शर्ट, जूते, मोजे, कम्बल, दरी, बरसाती, मच्छर दानी, जर्सी, अंगोला शर्ट एवं किट बाक्स, फोल्डिंग पलंग, इत्यादि सामग्रियां शामिल है। सम्पूर्ण सामग्री एक लाट में नीलामी की जाएगी। इच्छुक खरीददार नीलामी तिथि के एक दिन पूर्व कार्यालयीन समय आकर नीलामी की जाने वाली सामग्रियों को देख सकेगें।

01- प्रत्येक खरीददार को बोली लगाने के पूर्व रूपये 1000.00 (रूपये एक हजार) मात्र नगद प्रतिभूति राशि कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। जिन खरीददारों की बोली स्वीकार नही होगी उन्हे जमा की गई प्रतिभूति की राशि वापस कर दी जाएगी।

02- खरीददार की उच्चतम बोली पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा स्वीकार किये जाने पर नीलामी की सम्पूर्ण राशि जमा कर उसी दिन सम्पूर्ण सामग्री को उठाना होगा।

03- नीलामी बोली की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अधिकार नीलामी कमेटी को होगा।

जिला सेनानी
नगर सेना, उत्तर बस्तर
कांकेर

जी-262702599/3

क्या भूपेश पंजाब कांग्रेस के संकट को हल कर पाएंगे?

इकबाल सिंह चन्नी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई.एन.सी.) का इतिहास जितना पुराना और गौरवशाली है, उतना ही आंतरिक कलह, गुटबाजी और ऐतिहासिक विद्रोहों से भी भरा पड़ा है। 1885 में अपनी स्थापना से लेकर आज तक, कांग्रेस ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई बड़े उतार-चढ़ाव, गुटबाजी और दलीय विभाजन देखे हैं। वर्तमान में, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पी.पी.सी.सी.) एक बार फिर ऐसे ही गंभीर आंतरिक संकट से जूझ रही है। पार्टी उच्च कमान ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त करके एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बघेल अपने वर्तमान पंजाब दौरे के दौरान पंजाब कांग्रेस के बिखरे हुए गुटों को एकजुट कर पाएंगे या नहीं।

पंजाब कांग्रेस के लिए सबसे बुरा दौर 2021-2022 का रहा। तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सार्वजनिक कलह ने पार्टी को खोखला कर दिया। कैप्टन को मुख्यमंत्री पद छोडऩा पड़ा और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। हाईकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया लेकिन सिद्धू और चन्नी के बीच मतभेदों के कारण कांग्रेस को 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। आज भी पंजाब कांग्रेस की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। पार्टी के भीतर 2 मुख्य गुट उभर कर सामने आए हैं-1. संगठनात्मक गुट : वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में। 2.चुनाव प्रचार समिति गुट : जालंधर से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में। चन्नी के समर्थक खुले तौर पर राजा वडिंग को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे नाजुक समय में भूपेश बघेल उच्च कमान के दूत के रूप में पंजाब दौरे पर हैं। हालांकि उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को एकजुट करना और जमीनी स्तर पर कार्यकर्त्ताओं को संगठित करना बताया जा रहा है लेकिन असल मकसद पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी को खत्म करना है। कहा जा सकता है कि भूपेश बघेल एक अनुभवी नेता हैं और छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक सरकार चला चुके हैं। उनकी रणनीति और वर्तमान कार्यकाल के दौरान इसके परिणामों को 2 दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है-उनकी यात्रा के सकारात्मक पहलुओं पर गौर करें तो उन्होंने कड़े फैसले लिए हैं और स्पष्ट संदेश दिए हैं। बघेल ने पंजाब पहुंचते ही साफ कर दिया कि नेतृत्व का मुद्दा अब खत्म हो चुका है। उन्होंने घोषणा की कि राजा वडिंग् पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे, चुनाव राहुल गांधी के नाम पर लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद हाईकमान मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगा। इसके साथ ही, 'कुर्सी की दौड़' फिलहाल स्थगित हो गई है। बघेल ने सभी गुटों को व्यक्तिगत कलह छोड़कर 'हर बूथ, कांग्रेस मजबूत' अभियान में शामिल होने का निर्देश दिया है। यह कदम नेताओं का ध्यान आंतरिक कलह से हटाकर विपक्षी दलों पर केंद्रित करने में मददगार साबित हो सकता है।जन विद्रोह और असंतोष-बघेल के दौरे के बावजूद, पार्टी का अंदरूनी असंतोष शांत नहीं हुआ है। पटियाला, संगरूर और लुधियाना में रैलियों के दौरान चन्नी समर्थकों ने खुलेआम नारे लगाए। इसके अलावा, कई वरिष्ठ नेताओं ने महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठकों से दूरी बनाए रखी, जिससे संकेत मिलता है कि 'सब कुछ ठीक नहीं है'। आंतरिक गद्दारों की चुनौती-बघेल ने स्वयं नेताओं को पार्टी के राज लीक करने वाले 'आंतरिक गद्दारों' से सावधान रहने की चेतावनी दी है। इससे साबित होता है कि पार्टी के भीतर अविश्वास की भावना अभी भी बहुत गहरी है।

भाजपा से मोहभंग करार देने की दृष्टिहीनता भरी मानसिकता

मनोज कुमार अग्रवाल

मतदाता लोकतंत्र में भाग्य विधाता की भूमिका रखता है और यह भाग्य विधाता सभी राजनीतिक दलों को हद और दायरे में रखना जानता है अथवा इस तरह मान लीजिए कि मतदाता सत्ताधारी दल और विरोधी दलों का समय समय पर कान उमेट कर उन्हें दिशाहीन होने से बचाने का संकेत देता है।अब स्थिति यह है कि भाजपा ने उपचुनावों में दो सीट क्या गंवाई कुछ लोगों ने इसे भाजपा से मोहभंग करार अलापना शुरू कर दिया। लेकिन यह सिर्फ दृष्टिहीनता से अधिक कुछ नहीं है।

आपको बता दें हाल ही में बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की एक-एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे संख्या की दृष्टि से भले ही छोटे हों, लेकिन उनके राजनीतिक संकेत व्यापक हैं। बिहार की बांकीपुर सीट पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर भारतीय जनता पार्टी का लगभग तीन दशक पुराना गढ़ तोड़ दिया है। वहीं, मध्य प्रदेश की दत्तिया सीट कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने भाजपा से छीन ली, जबकि गुजरात की मांजलपुर सीट पर भाजपा ने 30 हजार से अधिक मतों के अंतर से अपना दबदबा बनाए रखा। इस प्रकार तीन राज्यों के जनादेश ने किसी एक दल के पक्ष में एकतरफा कहानी लिखने के बजाय तीन अलग-अलग राजनीतिक संदेश दिए हैं। सबसे अधिक चर्चा बिहार की बांकीपुर सीट की हो रही है। पटना के शहरी क्षेत्र में आने वाली यह सीट वर्ष 1995 से भाजपा के प्रभाव वाली मानी जाती रही है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के कारण यहां उपचुनाव कराया गया था। ऐसे मजबूत राजनीतिक दुर्ग में प्रशांत किशोर की 19 हजार से अधिक मतों से जीत केवल एक उम्मीदवार की सफलता नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प की संभावनाओं का उद्घोष है। प्रशांत किशोर अब तक चुनावी रणनीतिकार, राजनीतिक टिप्पणीकार और बिहार में पदयात्रा करने वाले अभियानकर्ता के रूप में पहचाने जाते थे। बांकीपुर के नतीजे ने पहली बार उन्हें निर्वाचित जनप्रतिनिधि और चुनाव जीत सकने वाले नेता की पहचान दी है। भारतीय राजनीति में सलाहकार से स्वयं चुनावी मैदान में उतरने की यात्रा आसान नहीं होती। दूसरे दलों को जिताने की रणनीति बनाना और

स्वयं जनता का भरोसा जीतना दो अलग-अलग चुनौतियां हैं। बांकीपुर की जीत से प्रशांत किशोर ने इस पहली परीक्षा को पार कर लिया है। फिर भी इस विजय को तत्काल पूरे बिहार में जन सुराज की लहर मान लेना जल्दबाजी होगी। बांकीपुर एक शहरी और अपेक्षाकृत विशिष्ट सामाजिक संरचना वाली सीट है। यहां मतदाताओं की प्राथमिकताएं ग्रामीण बिहार से भिन्न हो सकती हैं। प्रत्याशी की व्यक्तिगत पहचान, भाजपा के भीतर स्थानीय असंतोष, विपक्षी मतों का समीकरण और कम मतदान जैसे कारक भी परिणाम को प्रभावित करते हैं। इसलिए जन सुराज की वास्तविक परीक्षा तब होगी जब पार्टी को ग्रामीण, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़े मतदाताओं के बीच समान रूप से स्वीकार्यता साबित करनी होगी। इसके बावजूद यह परिणाम बिहार इसके बा के स्थापित राजनीतिक दलों के लिए चेतावनी तो जरूर है।

भाजपा को सोचना होगा कि वर्षों से सुरक्षित मानी जाने वाली सीट पर उसका संगठन और उम्मीदवार चयन क्यों कमजोर पड़ा। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लिए भी यह नतीजा असहज करने वाला है। भाजपा विरोधी मतदाता यदि पारंपरिक विपक्ष के बजाय एक नए विकल्प की ओर जाने लगें, तो बिहार की राजनीति का त्रिकोणीयकरण तेज हो सकता है। जन सुराज की मजबूती केवल भाजपा के लिए चुनौती नहीं होगी; वह विपक्षी दलों के मताधार में भी सेंध लगा सकती है। वहीं, मध्य प्रदेश की दतिया सीट का परिणाम कांग्रेस के लिए मनोवैज्ञानिक संबल है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा उम्मीदवार को पराजित कर वह सीट हासिल की। राज्य में सत्ता से बाहर कांग्रेस के लिए यह जीत बताती है कि मजबूत स्थानीय उम्मीदवार, संगठित प्रचार और जमीनी मुद्दों पर केंद्रित रणनीति के के माध्यम से भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। दतिया का नतीजा भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है। उपचुनाव सरकार बनाने या गिराने वाले नहीं होते, लेकिन वे सत्तारूढ़ दल के प्रति स्थानीय नाराजगी को खुलकर व्यक्त करने का अवसर देते हैं। मतदाता जानते हैं कि एक सीट हारने से सरकार नहीं बदलेगी, इसलिए वे स्थानीय प्रशासन, उम्मीदवार, विकास कार्यों और राजनीतिक व्यवहार के आधार पर अपेक्षाकृत स्वतंत्र मतदान कर सकते हैं।

दतिया में भाजपा की हार यही संकेत देती है कि सत्ता और मजबूत संगठन के बावजूद स्थानीय असंतोष की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कांग्रेस को भी इस जीत से अतिउत्साहित होने के बजाय सीख लेनी चाहिए। लंबे समय से पार्टी की कमजोरी उसका असंगठित स्थानीय ढांचा, गुटबाजी और चुनाव के समय सक्रिय होने की प्रवृत्ति रही है। दतिया की सफलता तभी राज्यव्यापी राजनीतिक लाभ में बदलेगी, जब कांग्रेस बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करे, स्थानीय नेतृत्व को महत्व दे और जनता के मुद्दों पर निरंतर आंदोलन करे। एक सीट की जीत आत्मविश्वास देती है, लेकिन स्थायी पुनरुत्थान के लिए निरंतरता आवश्यक है।

दूसरी ओर गुजरात की मांजलपुर सीट पर भाजपा की 30 हजार से अधिक मतों की जीत बिल्कुल अलग संदेश देती है। यह सीट भाजपा ने न केवल बचाई, बल्कि बड़े अंतर से जीतकर यह प्रदर्शित किया कि गुजरात के शहरी क्षेत्रों में उसका संगठन, सामाजिक गठबंधन और मतदाता आधार अब भी प्रभावी है। मांजलपुर पर भाजपा का कब्जा वर्ष 2012 से रहा है और इस उपचुनाव में भी कांग्रेस उसे गंभीर चुनौती नहीं दे सकी। गुजरात में भाजपा की सफलता का प्रमुख आधार उसका मजबूत बूथ प्रबंधन, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनाव को गंभीरता से लड़ने की संस्कृति रही है। जहां विपक्ष कई बार उपचुनाव को सीमित महत्व देता है, वहीं भाजपा छोटी से छोटी चुनावी लड़ाई को भी संगठन की परीक्षा मानती है।

मांजलपुर का परिणाम इसी चुनावी मशीनरी की मजबूती को रेखांकित करता है। कांग्रेस के लिए गुजरात का संदेश स्पष्ट है। केवल सत्ता विरोधी भावना की प्रतीक्षा करते रहने से भाजपा को पराजित नहीं किया जा सकता। विपक्ष को शहरी मतदाताओं के लिए ठोस आर्थिक, प्रशासनिक और विकास संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना होगा। उसे ऐसे स्थानीय चेहरे तैयार करने होंगे जो लंबे समय तक जनता के बीच काम करें। चुनाव के कुछ सप्ताह पहले उम्मीदवार उतारकर मजबूत संगठन का मुकाबला करना कठिन है।

तीनों नतीजों को एक साथ देखने पर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आता है कि मतदाता अब राजनीतिक गढ़ों को स्थायी नहीं मानता। बांकीपुर में भाजपा का दशकों पुराना प्रभाव समाप्त हुआ, दतिया में सत्तारूढ़ दल से सीट छिनी, लेकिन मांजलपुर में उसी भाजपा ने अपना किला और मजबूत कर लिया। इसका अर्थ है कि भारतीय मतदाता एक ही समय में परिवर्तन और निरंतरता दोनों के पक्ष में मतदान कर सकता है। इन उपचुनावों ने यह भी सिद्ध किया कि मतदाता राष्ट्रीय नेतृत्व, राज्य सरकार और स्थानीय उम्मीदवार का अलग-अलग मूल्यांकन करता है। किसी दल की राष्ट्रीय लोकप्रियता स्थानीय स्तर पर जीत की गारंटी नहीं है।

इसी प्रकार किसी एक सीट की हार से पूरे राज्य में दल की लोकप्रियता समाप्त नहीं मानी जा सकती। चुनाव का परिणाम उम्मीदवार की स्वीकार्यता, स्थानीय समीकरण, संगठन, प्रचार और मतदाताओं की तत्काल चिंताओं के संयुक्त प्रभाव से तय होता है। अंतत: इन नतीजों का सबसे बड़ा संदेश राजनीतिक दलों के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए है। मतदाता किसी सीट, क्षेत्र या समुदाय को किसी दल की स्थायी संपत्ति मानने को तैयार नहीं है। वह काम, उम्मीदवार और विश्वसनीय विकल्प के आधार पर अपना निर्णय बदल सकता है। यही लोकतंत्र की शक्ति है और यही तीन राज्यों के उपचुनावों का निचोड़ है ।

पुराण दिग्दर्शन ....

विश्व विद्या-निरुपणाध्याय: (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

यदि यूराल की मध्य चोटी पर उत्तर दक्षिण को दूसरी रेखा खींची जावे तो उसपर भी पृथ्वी के सूखे भाग की लम्बाई जितनी उत्तर को होगी ठीक उतनी ही दक्षिण को भी होगी। इसलिये वर्तमान समय में यूराल कहे जाने वाले पहाड़ को ही हमारी इस मत्यं पृथ्वी का सुमेरु कहा जाना चाहिये! क्योंकि पुराणों में सुमेरु को काँचनगिरि लिखा है अत: अन्वेषण करने पर उक्त पर्वत में अत्यधिक उज्ज्वल खरे सोने की खानें भी बहुतायत से प्राप्त हो सकती हैं- यह भी सुनिश्चित है।

हमारी पृथ्वी का परिमाण

जिस तरह सूर्य के ताप की सीमा पर्य्यन्त विस्तार वाले भूमण्डल का परिमाण पचास करोड़ योजन है ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी का परिमाण भी पचास करोड़ योजन ही है। शङ्का हो सकती है कि जब पूर्वोक्त अण्डमध्यगत: सूर्यो आदि प्रमाणों के अनुसार भूपिण्ड से लेकर सूर्य्यताप स्थान तक विस्तृत अन्तरिक्ष का परिमाण केवल पचास करोड़ योजन माना गया है फिर तदन्तर्गत अकिञ्चित्प्राय: भूपिण्डमात्र का परिमाण पचास करोड़ योजन कैसे हो सकता है? भूमण्डल और भूपिण्ड दोनों को ही पचास करोड़ योजन के मानना वैसा ही असम्भव जंचता है जैसे कोई कहे कि मेरे दादा के यहाँ एक छप्पन गज का हाल कमरा है जिसके एक छोटे से कोने में छप्पन गज का सन्दूक रक्खा है? भला अब विचारिये कि जब कमरा ही छप्पन गज का है फिर उसके सिर्फ एक ही कोने में छप्पन गज का संदूक कैसे समा सकता है? ठीक इसी प्रकार भूपिण्ड और भूमण्डल का तारतम्य समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष में भी वर्तमान गवेषकों ने हमारी इस पृथ्वी का परिमाण केवल 7667 मील निश्चित किया है जोकि सिर्फ एक हजार योजन के करीब ठहरता है।

क्रमश: ...

भारत छोड़ो आंदोलन ने हिला दी थी ब्रिटिश सरकार की नींव

अनन्या मिश्रा

आज यानी की 08 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई जा रही है। आज से करीब 84 साल पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को इस आंदोलन ने ही नई दिशा दी थी और इसके 5 साल बाद भारत को अंग्रेजो की गुलामी से आजादी मिल गई थी। भारत को आजादी हासिल करने में इस आंदोलन ने निर्णायक भूमिका अदा की थी। इसलिए 08 अगस्त के दिन को अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जाता है।

ब्रिटेन की सहमति के बिना भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया गया था। जिस वजह से भारतीयों में असंतोष बढ़ा था। साल 1942 में शुरू हुए क्रिप्स

मिशन की विफलता ने स्वतंत्रता सेनानियों को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। क्योंकि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने से ब्रिटिश सरकार ने साफ इनकार कर दिया था।

इसलिए 08 अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वतंत्रता सेनानियों को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में इकट्ठा किया। इस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। आंदोलन करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। टैंक मैदान को आज अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। भारत को स्वतंत्र कराएंगे या स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते हुए मर जाएंगे, यह नारा देते हुए स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सरकार से तत्काल भारत छोड़कर जाने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुई। लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 09 अगस्त 1942 को जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। इस आंदोलन में करीब 1 लाख लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी।

भारत छोड़ो आंदोलन में लाखों लोगों की जन भागीदारी हुई थी। यह आंदोलन जनता का आंदोलन बन गया। इसमें किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं और नौजवान शामिल हुए थे। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और ऊषा मेहता जैसे नेताओं ने की थी। वहीं इन नेताओं ने आंदोलन के दौरान गिरफ्तारियां भी दी थीं। वहीं ऊषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो चलाकर इस आंदोलन को प्रचारित किया है। हालांकि यह आंदोलन अहिंसक था, लेकिन रेलवे स्टेशनों और डाकघरों पर हमले किए गए थे। वहीं ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की भरपूर कोशिश की थी।

बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन ने अंतरराष्ट्रीय समुदायों का ध्यान खींचा। विश्व युद्ध में भी ब्रिटेन कमजोर पड़ने लगा था। इस आंदोलन ने भारतीयों में आजादी की ललक जगाई थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को तत्काल दबा दिया था। लेकिन इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी थीं।

किस पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे मुनीर-शहबाज?

अभिनय आकाश

राजनीतिक अनिश्चितता, सीमा पार से बढ़ता आतंकवाद और सड़कों पर भड़कता जन-आक्रोश पाकिस्तान इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर गंभीर संकट से जूझ रहा है। तस्वीर साफ़ है। एक कब्जे वाले इलाके में कराया गया दिखावटी चुनाव, खून-खराबे में तब्दील होते सड़कों के विरोध-प्रदर्शन, पुलिस थानों पर बरसाती गोलियों वाले सिरफिरे आतंकी, और सेना के इशारों पर नाचती सरकार की धज्जियां उड़ाते विद्रोही! गजब की बात तो यह है कि कभी जिनके दम पर पाकिस्तान उछलता था, आज वही पुराने दोस्त उसके सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं। सोने पर सुहागा यह कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री की एक आवाज पर आज भी सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ता है और हालत यह आ चुकी है कि खुद सरकार भी मान रही है कि सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। कहानी की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) से करते हैं। इस्लामाबाद की सरकार ने सोचा था कि 10 अगस्त तक निपटाने के लिए यहाँ एक ढर्रे वाला लोकल इलेक्शन करा देंगे। लेकिन नेताओं की रैलियों की जगह, पाकिस्तान के गैर-कानूनी कब्जे में पिस रही जनता ने यह पूरी गर्मी सड़कों के उग्र आंदोलनों में बिता दी। इस पूरे बवाल के केंद्र में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएसी) खड़ा है। शुरुआत बहुत सीधी-सादी मांगों सस्ती बिजली, सब्सिडी वाला आटा, टैक्स में छूट और शासन में सही नुमाइंदगी से हुई थी। लेकिन अब यह चिंगारी पूरे पाकिस्तान के लिए ऐसा नासूर बन चुकी है, जिसे बुझाना इस्लामाबाद के बस के बाहर की बात दिख रही है!

समय के साथ, इसकी मांगें एक बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गईं। सबसे विस्फोटक मांग थी। स्थानीय विधानसभा में बाहरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करना। जेएसी का तर्क है कि इन सीटों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोगों की राजनीतिक आवाज़ कमजोर होती है। बढ़ते गुस्से पर इस्लामाबाद की

प्रतिक्रिया मजबूरी में आई है। सुरक्षा बलों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर स्नाइपर से गोलीबारी की है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कम से कम 90 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। हाल के हफ्तों में कर्फ्यू, रास्ते बंद करने और कार्यकर्ताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के साथ सख्ती और बढ़ गई है। अशांति और सख्ती के इसी माहौल में इस्लामाबाद अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थानीय चुनाव करा रहा है। लेकिन वोटिंग पूरी होने से पहले ही, स्थानीय कार्यकर्ता इन चुनावों को धांधली वाला बता रहे हैं। वे जेएसी को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने को गलत कदम मानते हैं। लेकिन सड़कों पर उतरे आम लोगों के लिए, सरकार के रवैये ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को अब आतंकवादी बताया जा रहा है। उनका कहना है कि इस लेबल का इस्तेमाल उनके विरोध को आपराधिक ठहराने के लिए किया जा रहा है।

पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे क्वेटा बलूचिस्तान का इलाका वैसे तो लगभग 45% क्षेत्र में फैला है। ईरान से इसकी सीमा भी लगती है। बलूचिस्तान में दूर दूर तक खाली मैदान और रेगिस्तान हैं। यहां की वीरानगी में इन दिनों बागी तेवर और तेज हो गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के लड़ाके अलग देश की मांग कर रहे हैं। हालात ये हैं कि बलूच लड़ाकों और पश्तून (पठान) विद्रोहियों का बलूचिस्तान सूबे के लगभग 70% हिस्से पर कब्जा है। अब सवाल केवल यह नहीं है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल कितने विद्रोहियों को ढेर करते हैं या गिरफ्तार करते हैं। असली सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी सरकार पुलिस स्टेशन खुले रख सकती है, हाईवे पर यातायात चला सकती है, बाजार और कारोबार सामान्य रख सकती है और लोगों को बिना डर के यात्रा करने की सुरक्षा दे सकती है? बलूचिस्तान के कई इलाकों में हथियारबंद लड़ाके क्वेटा, खुजदार और मसतुंग जैसे शहरों में घुसकर पुलिस थानों और सरकारी दफ्तरों पर हमले करते हैं। बीएलए के लड़ाके और पश्तून गुट सड़कों पर अस्थायी चौकियां बना रहे हैं और वाहनों की तलाशी लेते हैं। खुलेआम वसूली भी होती है।

बलूचिस्तान को पाकिस्तान की खनिजों की खदान भी कहते हैं। बात शुरू की तो खुजदार शहर के युवक मोमिन का पाक सरकार पर गुस्सा फूट पड़ा। मोमिन कहते हैं यहां के ग्वादर पोर्ट पर चीन का कब्जा है। चीन ने सीपैक के नाम पर यहां लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। ग्वादर पोर्ट पर चीन की फिशिंग बोट्स का कब्जा है। स्थानीय बलूच मछुआरों को चीनी बोट्स खदेड़ देती हैं। इनकी बोट्स बड़ी और ज्यादा पावर वाली होती हैं। ज्यादातर बलूच मछुआरों के पास अब भी पालदार नौकाएं हैं। बलूच बेरोजगार हो रहे हैं। 55 साल के असलम का कहना है कि यहां के रेअर अर्थ मिनरल पर अमेरिका का कब्जा है। पाक आर्मी चीफ मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के सामने मिनरल की नुमाइश करते हैं। इस खजाने पर केवल बलूचों का हक है।

खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का फ्रंटियर यानी सरहदी इलाका है। डूरंड लाइन पाक और अफगानिस्तान को अलग करती है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के पांच साल में खैबर के अधिकांश इलाके में इन्हीं का दबदबा है। 2 अगस्त को पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांत में आतंकवाद-विरोधी रैली के दौरान हुए आत्मघाती बम धमाके में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और दो दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। मरने वालों में ज़्यादातर आम नागरिक और पुलिस अधिकारी थे। यह हमला प्रांत की स्वात घाटी के काबल शहर में हुआ, जहाँ प्रदर्शनकारी एक पुलिस स्टेशन के पास जमा होकर नारे लगा रहे थे और घाटी में शांति और अमन की मांग कर रहे थे। स्वात पीस रैली नाम की इस रैली का आयोजन स्थानीय आदिवासी परिषद स्वात अमन जिरगा ने किया था। यह बम धमाका पाकिस्तान के लिए आंतरिक सुरक्षा और जान-माल के नुकसान के लिहाज़ से बेहद गंभीर रहे साल की एक और घटना है। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान सशस्त्र बलों के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार (31 जुलाई) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2026 में पाकिस्तान में आतंकवाद की 3,145 घटनाएं हुईं, जिनमें से 1,971 घटनाएं केपी में हुईं। जुलाई 2026 तक, आतंकवादी घटनाओं में 800 से ज़्यादा पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं, जिनमें 300 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। खैबर में पाक सरकार के कानून नहीं तालिबान का शरिया चलता है। दरअसल, इस इलाके में विभाजन के समय से ही कबिलाई व्यवस्था लागू रही है। स्वात, सैदू, मिंगोरा और मर्दन में लोया जिरगा के जरिए ही कानून चलता है। ये जिस जगह असल में शरिया कानून को लागू करती है। अफगान तालिबान इसका है। इमरान खान की सरकार ने 2021 में टीटीपी के साथ सुलह की कोशिश की, लेकिन इमरान की गद्दी जाते ही टीटीपी ने खैबर में अपने दबदबे को और बढ़ा लिया है। खैबर के वजीरिस्तान में पाकिस्तान सेना कई सैन्य ऑपरेशन कर चुकी है, लेकिन यहां अब टीटीपी काबिज है। आए दिन टीटीपी के हमलों के कारण स्कूल और कॉलेज बंद रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के आए दिन होने वाले हमलों से पाक सेना में खौफ है। इस साल टीटीपी फौज पर 145 से ज्यादा हमले कर चुकी है, इनमें 48 सैनिक मारे गए। खैबर में डूरंड लाइन पर अभी पाक सेना की 50 फौजी चौकियां खाली हैं। 22 पोस्ट पर ही पाक फौज तैनात है।

आज का इतिहास

1509 विजय नगर सम्राज्य के सम्राट के रूप में महाराज कृष्णदेव राय की ताजपोशी।
1549 फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
1609 वेनिस की सीनेट ने गैलिलियो द्वारा तैयार दूरबीन का निरीक्षण किया।
1763 वर्षों के संघर्ष के बाद अंततः कनाडा फ्रांस के अधिकार से स्वतंत्र हुआ।
1864 जिनेवा में रेड क्रॉस की स्थापना।
1876 थॉमस अल्वा एडिसन ने मिमियोग्राफ का पेटेंट कराया।
1899 ए.टी. मार्शल ने रेफ्रीजरेटर का पेटेंट कराया।
1900 बोस्टन में पहली डेविस कप श्रृंखला की शुरूआत।
1908 शास्त्रीय संगीत गायिका सिद्धेश्वरी देवी का जन्म।
1919 ब्रिटेन ने अफगानिस्तान की आजादी को मंजूरी दी।
1942 महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की।
1945 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ ने लंदन एग्रीमेंट पर साइन किए। दुनियाभर के वॉर क्रिमिनल्स पर ट्रायल चलाने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया था।
1947 पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी।
1963 ग्लासगो से लंदन जा रही रॉयल मेल ट्रेन को हथियारबंद लुटेरों ने लूट लिया। लुटेरों ने 2.6 मिलियन यूरो की राशि लूटी। ब्रिटेन में इसे द ग्रेट ट्रेन रॉबरी कहा जाता है।
1974 वाटरगेट स्कैंडल में अपनी भूमिका के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस्तीफा देने की घोषणा की। अगले ही दिन निक्सन ने इस्तीफा दे दिया।
1988 अफगानिस्तान में 9 साल के युद्ध के बाद रूसी सेना की वापसी शुरू हुई।
1988 आठ वर्ष तक चले संघर्ष के बाद ईरान और इराक के बीच युद्धविराम की घोषणा।
1990 इराक़ के तत्कालीन तानाशाह सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जे का ऐलान किया।
2002 ताइवान आज़ाद होने के लिए जनमत संग्रह योजना से पीछे हटा।
2003 पन्द्रह छोटे देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ताइवान की सदस्यता का समर्थन किया।
2004 जापान ने चीन को पराजित करके एशिया कप फ़ुटबाल जीता।
2007 एक्सनाना गुसमाओ पूर्वी तिमोर के प्रधानमंत्री बने।
2008 चीन के बीजिंग में ओलिंपिक खेलों की शुरुआत हुई।
2010 तेजस्विनी सावंत म्युनिख में आयोजित विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनीं।

अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान को मोदी ने खुद आगे आकर दिया करारा जवाब

नीरज कुमार दुबे

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की सातवीं वर्षगांठ पर पाकिस्तान ने एक बार फिर पुराना राग अलापने की कोशिश की, लेकिन उसकी इस बदजुबानी का करारा जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि 5 अगस्त 2019 का ऐतिहासिक फैसला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए एक निर्णायक नए युग की शुरुआत था। उन्होंने दो टूक कहा कि बीते सात वर्षों में इन दोनों क्षेत्रों ने विकास, सुशासन और सामाजिक सशक्तिकरण के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया, जब पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने भारत के इस संवैधानिक फैसले को लेकर फिर से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच %एक्स% पर अपने संदेश में कहा कि सात वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 और 35ए इतिहास बन गए थे और इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के विकास का नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि वर्षों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रहे महिलाओं, अनुसूचित वर्गों और अन्य वंचित समुदायों को अब भारतीय संविधान का पूरा संरक्षण और अधिकार मिला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, उद्यमिता और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और केंद्र सरकार इन क्षेत्रों को विकसित भारत की यात्रा का मजबूत भागीदार बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस वर्ष अनुच्छेद 370 हटाए जाने की वर्षगांठ इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के वर्ष में पड़ रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए डॉ. मुखर्जी ने जिस संकल्प का सपना देखा था, वह 5 अगस्त 2019 को साकार हुआ।

दूसरी ओर, पाकिस्तान ने एक बार फिर 5 अगस्त को तथाकथित %यौम-ए-इस्तेहसाल% के रूप में मनाते हुए भारत के खिलाफ बयानबाजी की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने दावा किया कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान

कश्मीर के लोगों को अपना नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन जारी रखेगा तथा इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहेगा।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इसी सुर में बयान देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर विवाद का समाधान पाकिस्तान की विदेश नीति का प्रमुख आधार बना रहेगा। उन्होंने भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की। वहीं उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी भारत के 5 अगस्त 2019 के फैसले को एकतरफा बताते हुए संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाने की मांग दोहराई। कुल मिलाकर देखें तो पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर वही पुराने आरोप लगाए, जिन्हें भारत लगातार खारिज करता रहा है।

हालांकि पाकिस्तान की यह बयानबाज़ी इसलिए भी खोखली और दोगली नजर आती है क्योंकि जो देश कश्मीरियों के अधिकारों की दुहाई देता है, वही पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में अपने ही कब्जे वाले इलाके के लोगों पर दमनचक्र चला रहा है। हाल ही में खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पीओजेके में आंदोलन कर रहे स्थानीय लोगों को भारत की तरह पाकिस्तान का दुश्मन तक करार दिया। पीओजेके में असीम मुनीर के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिन्हें दबाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है। कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं, बिजली की आपूर्ति बाधित की गई, राशन और आवश्यक सुविधाओं पर भी असर पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनकी आवाज को बलपूर्वक कुचला जा रहा है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि जो पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा, वह जम्मू-कश्मीर के लोगों की चिंता जताने का नैतिक अधिकार कैसे रखता है? स्पष्ट है कि कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान की राजनीति महज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रचार और दुष्प्रचार तक सीमित रह गई है।

दूसरी ओर, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में विकास परियोजनाओं को तेज गति मिली है। श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जैसी वैश्विक पहचान मिली है। डल झील में संगीत फव्वारे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हैं। वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी ने क्षेत्र में बढ़े विश्वास और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टि की है। सड़क, रेल और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, शिक्षा और उद्यमिता के नए अवसर पैदा हुए हैं तथा स्थानीय हस्तशिल्प और पर्यटन उद्योग को नई ऊर्जा मिली है। पत्थरबाजी खत्म हो गयी है, अलगाववादी टूट चुके हैं और आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और लाल चौक पर तिरंगा शान से लहरा रहा है।

बहरहाल, सात वर्षों बाद तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक ओर पाकिस्तान है, जो अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही दमन, इंटरनेट बंदी, बिजली कटौती और सैन्य कार्रवाई के साये में जीने को मजबूर कर रहा है, जबकि दूसरी ओर भारत का मुकुट जम्मू-कश्मीर है, जो विकास, निवेश, पर्यटन, रोजगार और सुशासन की नई पहचान बना रहा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया 5 अगस्त 2019 का ऐतिहासिक निर्णय केवल एक संवैधानिक बदलाव नहीं था, बल्कि जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद और पिछड़ेपन के दौर से निकालकर विकास और राष्ट्रीय एकीकरण की मुख्यधारा में लाने वाला निर्णायक मोड़ साबित हुआ। यही वजह है कि आज पाकिस्तान के आरोपों से अधिक प्रभावशाली वह बदली हुई तस्वीर है, जिसे जम्मू-कश्मीर की धरती पर विकास, शांति और जनविश्वास के रूप में पूरी दुनिया देख रही है।

शेख हसीना को लेकर भारत पर भड़कता बांग्लादेश

शोभना जैन

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की हाल ही में नई दिल्ली में वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से बांग्लादेश सरकार न केवल हसीना से बल्कि भारत से बुरी तरह से तमतमा गई हैं, जब कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले भी भारत सरकार का साफ तौर पर कहना था कि विदेशी संवाददाता के क्लब द्वारा आयोजित हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनका कोई संबंध नही हैं। हालांकि, पिछले दो सालों में यह पहली बार है जब उन्होंने वर्चुअल माध्यम से सीधे पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया।बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में सीधे मीडिया से बातचीत की अनुमति दिए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है।

अगस्त 2024 में हसीना ने बांग्लादेश में चल रहे तत्कालीन अशांत और उपद्रवकारी हालात के मद्देनजर अपनी सुरक्षा को लेकर मानवीय आधार पर भारत से शरण मांगी थी। उसके बाद से वे भारत में ही रह रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर दो वर्ष पूर्व भारत द्वारा शरण दिए जाने के बाद से बांग्लादेश और भारत के बीच चल रहे असहज रिश्ते और भी असहज हो गए हैं।

बांग्लादेश ने शेख हसीना को वापस स्वदेश भेजे जाने (प्रत्यर्पण) की मांग को दोहराते हुए कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष से बार-बार इस तरह के आग्रह का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, जबकि भारत का कहना है कि यह आग्रह उसके विचाराधीन है। बांग्लादेश हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस कदर क्षुब्ध हुआ कि उसने राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों को चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की तो उनके खिलाफ न्यायपालिका का इस्तेमाल कर मुकदमे दायर किए जाएंगे।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की

सजा सुनाई जा चुकी है। वे पांच अगस्त 2024 को सत्ता से हटाए जाने के बाद से ही भारत में हैं। अपने देश में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद पिछले दो साल से भारत में शरणागत शेख हसीना ने कहा कि वे जानती हैं स्वदेश लौटने पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है,

मुकदमा चल सकता है या फर्जी मामलों में फंसा सकते हैं लेकिन यह भय उन्हें अपने दायित्व निभाने से रोक नहीं सकता है। उन्होंने आगामी दिसंबर में अपने समर्थकों के साथ स्वदेश लौटने की इच्छा जताई है। शेख हसीना कह चुकी हैं कि उनके लौटने की इच्छा निजी है और भारत ने उन्हें पूरे सम्मान और आदर से अपने यहां रखा।

अगर वह वाकई दिसंबर में लौट जाती हैं, तो भारत के लिए बांग्लादेश के साथ संबंधों को सामान्य गति से आगे बढ़ाना शायद आसान हो जाए, क्योंकि शेख हसीना को शरण देने की 'असुविधाजनक स्थिति' कूटनीति पर असर नहीं डालेगी। हसीना के कार्यकाल में भारत के साथ बांग्लादेश के सहज मैत्रीपूर्ण संबंध रहे थे। मौजूदा समय में बांग्लादेश से भारत के रिश्ते खासे असहज चल रहे हैं, ऐसे में सरकार के विरोधी रुख के साथ-साथ हसीना की वापसी पर कुल मिलाकर बांग्लादेश के लोग क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, इसी पर दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते तय होंगे।

परीक्षा लीक से नहीं, पुरानी 'एकाधिकार व्यवस्था' से लड़ें

एम. मुनीर

भारत ने परीक्षा धोखाधड़ी के खिलाफ जंग छेड़ दी है। पेपर लीक के मामले में अब जेल की अधिक सख्त सजा होगी। संगठित नकल सिंडिकेटों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। जांच प्रक्रिया तेज होगी। विशेष अदालतें त्वरित न्याय प्रदान करेंगी। संसद ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि परीक्षाएं किसी क्राइम थ्रिलर जैसी लगने लगें, तो शायद आपराधिक कानून को इसमें बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन क्या हो, अगर पेपर लीक बीमारी ही न हो? क्या होगा अगर परीक्षा प्रणाली खुद ही एक बीमारी हो? हर साल, लाखों छात्र अपनी किशोरावस्था एक ऐसी परीक्षा की तैयारी में लगा देते हैं, जो सिर्फ कुछ घंटों तक चलती है लेकिन अगले 40 वर्षों के उनके करियर का मार्ग तय करती है। फिर जब प्रश्नपत्र लीक होता है, तो हम हैरान होने का नाटक करते हैं। अत्यधिक जोखिम वाली प्रणालियां अक्सर बड़े अपराधों को जन्म देती हैं।

भारत का कोचिंग उद्योग करियर की चिंता और आशंकाओं पर फलता-फूलता है और यह हमारी प्रवेश प्रणाली के कारण अस्तित्व में है। इसका वार्षिक राजस्व 60,000 करोड़ रुपए अनुमानित है और इसके लगातार बढ़ने की उम्मीद है। परिवार अनिवार्य रूप से एक 'लॉटरी' के लिए प्रति माह 50,000 रुपए से अधिक खर्च करते हैं और कुछ तो इसके लिए ऋण भी लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस (ए.आई.) अब भारत को 1947 के बाद से अपने सबसे मौलिक शैक्षिक सुधारों को लागू करने और देश के परीक्षा दर्शन में संशोधन करने का अवसर देती है।

पहला विचार सरल है। इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता

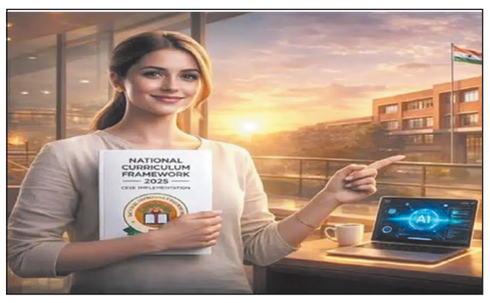

वाले पैनल को यह सिफारिश करके शुरुआत करनी चाहिए कि उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में कई अवसर दिए जाएं। विशिष्ट संस्थानों में प्रवेश चाहने वाले छात्रों को हर महीने सुरक्षित कम्प्यूटर-आधारित परीक्षाएं देने में सक्षम होना चाहिए और रैंकिंग के लिए उनका सर्वोत्तम स्कोर स्वतः ही चुन लिया जाना चाहिए। ए.आई. संचालित निगरानी, एन्क्रिप्टेड प्रश्न बैंक और एडाप्टिव टैस्ट प्रोटोकॉल इसे संभव बनाते हैं। बहु-अवसर प्रणाली पेपर लीक के प्रोत्साहन को कम करती है क्योंकि कोई भी एक परीक्षा जीवन का अंतिम और एकमात्र फैसला नहीं होती। दूसरा, एक समान प्रश्नपत्रों को समाप्त करें। प्रत्येक उम्मीदवार को एक सत्यापित और हैक-प्रूफ प्रश्न बैंक से ए.आई. द्वारा यादृच्छिक (रैंडमाइज्ड) रूप से तैयार किए गए अद्वितीय प्रश्न मिलने चाहिएं, जो समान कठिनाई स्तरों के लिए कैलिब्रेट किए गए हों। यदि हर प्रश्नपत्र अलग है, तो लीक हुआ पेपर खरीदना जीतने वाले नंबर के घोषित होने के बाद लॉटरी टिकट चुराने जैसा निरर्थक हो जाएगा।

तीसरा, यह नाटक करना बंद करें कि स्मरण शक्ति ही बुद्धिमता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल अनगिनत ज्ञान परीक्षणों में पहले से ही मनुष्यों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारी परीक्षाओं को तदनुसार विकसित होना चाहिए। छात्रों को स्मार्टफोन पर आसानी से उपलब्ध फॉर्मूले याद करने के लिए कहने की बजाय, इस बात का परीक्षण करें कि वे अपरिचित समस्याओं को कैसे हल करते हैं, ए.आई. जैनरेटेड उत्तरों का मूल्यांकन कैसे करते हैं, मतिभ्रम का पता कैसे लगाते हैं, डाटा की व्याख्या कैसे करते हैं और बुद्धिमान प्रणालियों के साथ जिम्मेदारी से सहयोग कैसे करते हैं। कल का इंजीनियर ए.आई. की दुनिया में काम करेगा और उसे यह पहचानने में सक्षम होना चाहिए कि कहां और कैसे गड़बड़ी हो रही है।

चौथा, एक 'अकादमिक क्रैडिट पासपोर्ट' बनाएं। छात्र एक निश्चित समय अवधि में कई परीक्षाओं, परियोजनाओं, इंटर्नशिप, हैकाथॉन, शोध कार्य, सामुदायिक सेवा और व्यावहारिक मूल्यांकनों में अंक जमा करेंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय एक दर्दनाक रविवार की सुबह के प्रदर्शन की बजाय छात्र के पूरे पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करेंगे। पांचवां, ए.आई. से प्रतिभा की पहचान करने को कहें, न कि केवल नकल पकड़ने को। परीक्षा प्रणालियां व्यावहारिक डाटा उत्पन्न कर सकती हैं। छात्र कठिन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, वे गलतियों से कितनी जल्दी उबरते हैं और क्या वे लगातार सुधार करते हैं-उदाहरण के लिए, वे कैसे तर्क देते हैं। यदि नैतिक और पारदर्शी तरीके से उपयोग किया जाए, तो ए.आई. लचीलेपन, रचनात्मकता और सीखने की क्षमता की पहचान कर सकता है, जो वास्तव में मायने रखती है।

छठा, और यह कोचिंग उद्योग को डरा देगा, विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता दें। हर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एक जैसे प्रवेश मानदंड क्यों होने चाहिएं? कुछ संस्थान नवाचार पर जोर दे सकते हैं, अन्य उद्यमिता, अनुसंधान क्षमता या व्यावहारिक योग्यता पर। जब हर संस्थान एक ही प्रवेश परीक्षा का उपयोग करता है, तो उसके लिए तैयारी करने का मतलब खुद को एक आम सांचे में ढालना होता है। हालांकि यह एकरूपता पेच बनाने वाले कारखानों के अनुकूल हो सकती है लेकिन यह मानवीय प्रतिभा के विविधीकरण को बढ़ावा नहीं देती, जो आगे चलकर अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि परीक्षाएं साल भर दी जा सकें, हर प्रश्न पत्र अद्वितीय हो, प्रवेश व्यापक मानदंडों द्वारा तय हो, रटने की बजाय तर्क का मूल्यांकन हो और विश्वविद्यालय विविध ताकतों की तलाश करें, तो कोचिंग सैंटरों को एक असाधारण बदलाव से गुजरना होगा। परीक्षा के गुर सिखाने की बजाय, उन्हें वास्तव में पढ़ाना पड़ेगा।

धोखाधड़ी विरोधी कानूनों को सख्त करने वाले भारत के संशोधन आवश्यक हैं क्योंकि संगठित पेपर लीक जनता के विश्वास को खतरे में डालते हैं और वे कठोर सजा के हकदार हैं। लेकिन कल की परीक्षा प्रणाली पुलिसिंग के जरिए भविष्य की शिक्षा चुनौती को हल नहीं कर पाएगी। नकलचियों को पकड़ना और लीक-पेपर बाजार पर नकेल कसना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि एक ऐसी परीक्षा प्रणाली तैयार करना, जो नकल को व्यावसायिक रूप से निरर्थक बना दे, कोचिंग के एकाधिकार को समाप्त कर दे और याद रखने की क्षमता से अधिक जिज्ञासा को मूल्यवान बनाए।

सत्ता बदली, लेकिन जो सबसे पहले बदलना था वह नहीं बदला

सत्येंद्र प्रताप सिंह

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन को अभी कुछ ही सप्ताह हुए हैं, लेकिन राजनीति की उस संस्कृति को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जिसके खिलाफ जनता ने बदलाव का जनादेश दिया था। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शमीक भट्टाचार्य को बार-बार अपनी ही पार्टी के लोगों को चेतावनी देनी पड़ रही है कि तोलाबाजी, कटमनी और जबरन घर-दुकान पर कब्जे की प्रवृत्ति तत्काल बंद हो। वह समयसीमा भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनका स्पष्ट कहना है कि भाजपा की राजनीतिक संस्कृति ऐसी नहीं है।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन चेतावनियों का असर जमीन पर कितना दिखाई दे रहा है। चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए लोगों के एक हिस्से पर फिलहाल इसका रत्ती भर असर पड़ता दिखाई नहीं देता। यह स्थिति भाजपा के लिए इसलिए अधिक गंभीर है, क्योंकि इनमें ऐसे लोग भी हैं जिनकी राजनीतिक पहचान कल तक उसी व्यवस्था से जुड़ी थी, जिसके खिलाफ भाजपा ने लंबे समय तक आंदोलन किया।

राजनीतिक दल बदलना आसान है, राजनीतिक संस्कार बदलना कठिन। किसी व्यक्ति के हाथ में पार्टी का झंडा बदल जाने से उसकी कार्यशैली और राजनीतिक संस्कृति अपने आप नहीं बदल जाती। यही वह चुनौती है जिसका सामना आज पश्चिम बंगाल में भाजपा को करना पड़ रहा है।

तृणमूल कांग्रेस की लगभग डेढ़ दशक की सत्ता के दौरान तोलाबाजी, कटमनी, राजनीतिक संरक्षण में जमीन और संपत्ति पर कब्जे तथा स्थानीय स्तर पर दबंगई जैसे आरोप उसकी छवि से जुड़ते चले गए। यही मुद्दे धीरे-धीरे उसके खिलाफ राजनीतिक असंतोष का कारण बने। जनता ने सत्ता परिवर्तन किया तो उसके पीछे केवल सरकार बदलने की इच्छा नहीं थी, बल्कि शासन और राजनीतिक व्यवहार में बदलाव की

अपेक्षा भी थी।

ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती केवल तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने तक सीमित नहीं है। असली परीक्षा यह साबित करने की है कि भाजपा उसी राजनीतिक संस्कृति का नया चेहरा नहीं बनेगी।

तृणमूल कांग्रेस को इन आरोपों और शिकायतों के बीच सत्ता में करीब 15 साल मिले। भाजपा को सत्ता संभाले अभी 15 सप्ताह भी पूरे नहीं हुए हैं और उसके प्रदेश अध्यक्ष को सार्वजनिक रूप से यह कहना पड़ रहा है कि तोलाबाजी और कटमनी बंद करो, लोगों के घर-दुकान पर कब्जा मत करो।

समय का यह अंतर अपने आप में महत्वपूर्ण है। किसी नई सरकार के शुरुआती दौर में ऐसी शिकायतें सामने आना और पार्टी नेतृत्व को तत्काल चेतावनी जारी करनी पड़ना इस बात का संकेत है कि सत्ता परिवर्तन के साथ पुराने राजनीतिक नेटवर्क और हित पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं।

भाजपा की पहली चुनौती संगठनात्मक है। उसे यह तय करना होगा कि तृणमूल से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल केवल चुनावी गणित के लिए किया जाए या उन्हें पार्टी की घोषित राजनीतिक संस्कृति में ढाला भी जाए।

दूसरी चुनौती नैतिक और राजनीतिक है। भाजपा ने जिस व्यवस्था के खिलाफ जनता से वोट मांगे, यदि उसी व्यवस्था की शिकायतें उसके शासन में भी सुनाई देने लगें तो जनता के लिए दोनों में अंतर करना मुश्किल होगा।

यही कारण है कि शमीक भट्टाचार्य की चेतावनियां केवल अनुशासन का मामला नहीं हैं। वे भाजपा की विश्वसनीयता की परीक्षा भी हैं। अगर पार्टी वास्तव में मानती है कि तोलाबाजी, कटमनी और कब्जे की राजनीति उसकी संस्कृति नहीं है तो उसे यह बात केवल भाषणों में नहीं, कार्रवाई के जरिए साबित करनी होगी।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से बड़ा बदलाव है, लेकिन लोकतांत्रिक बदलाव की असली सफलता तभी मानी जाएगी जब शासन की कार्यशैली भी बदले। जनता ने यदि एक राजनीतिक संस्कृति को खारिज किया है तो उसके सबसे विवादित तौर-तरीकों को नए राजनीतिक झंडे के नीचे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

भाजपा के सामने अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए कि वह जनता को यह भरोसा दिला सकती है कि सत्ता परिवर्तन का अर्थ केवल शासक का बदलना नहीं, बल्कि शासन के तौर-तरीकों का बदलना भी है। चुनौती इसलिए कि चुनाव के समय दूसरे दलों से आए लोगों को साथ लेते हुए वह अपनी राजनीतिक पहचान और अनुशासन को कमजोर न होने दे।

तृणमूल कांग्रेस ने करीब 15 साल सत्ता में रहकर जिन गलतियों की राजनीतिक कीमत चुकाई, भाजपा को उनसे सीखने के लिए 15 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर वही शिकायतें सत्ता परिवर्तन के महज 15 सप्ताह के भीतर उसके खिलाफ उठने लगें तो यह नई सरकार के लिए गंभीर चेतावनी है।

पश्चिम बंगाल में सवाल अब यह नहीं है कि सत्ता किसकी है। सवाल यह है कि सत्ता की संस्कृति किसकी होगी। अगर झंडा बदल गया लेकिन तोलाबाजी, कटमनी और दबंगई का तरीका नहीं बदला, तो फिर सत्ता परिवर्तन अधूरा ही माना जाएगा।

गांधी परिवार की तुलना में संघ परिवार कहीं अधिक लोकतांत्रिक'

दिव्या ए.

राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) से इस्तीफा देने के कुछ ही हफ्तों बाद हाल ही में भाजपा में शामिल हुई हैं। टी.एम.सी. में उनका कार्यकाल 5 साल तक रहा, जो उससे पहले कांग्रेस के साथ उनके दशकों लंबे जुड़ाव से काफी छोटा था। सुष्मिता ने अपने पूर्व दलों से मोहभंग के कारणों, नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन से सरकार के निपटने के तरीके और आर.एस.एस. के बारे में बात की। तीन राजनीतिक दलों में रहीं सुष्मिता ने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एन.एस.यू.आई., जो कि कांग्रेस की छात्र इकाई है, से छात्र राजनीति के रूप में की थी और 2021 में इसे छोड़ दिया। तो, कांग्रेस से तृणमूल में जाना कोई वैचारिक बदलाव नहीं था..., ममता दीदी ने खुद कांग्रेस छोड़कर इस पार्टी का गठन किया था। उन्हें बहुत जल्दी यह अहसास हुआ कि बंगाल या देश में कहीं भी टी.एम.सी. का वोट-शेयर वैचारिक नहीं है, यह नेता-केंद्रित है। इसके विपरीत, कांग्रेस का एक वैचारिक आधार है, अगर आप भाजपा को पसंद नहीं करते हैं, तो आप कांग्रेस को वोट देते हैं। लेकिन भाजपा का वोट पूरी तरह से वैचारिक है। जब उनके पास दो सांसद थे या जब उनके पास एक भी सांसद नहीं था और आज जब वे सत्ता पक्ष में हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर चुनाव के बाद कई समीक्षा बैठकें करती है। इसलिए, यह लोकतांत्रिक प्रतीत होती है लेकिन जब कार्यान्वयन की बात आती है, तो आंतरिक सहमति की कमी होती है। और तृणमूल में, चर्चा के लिए शायद ही कोई मंच हो। सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित है, क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाई और इसे चलाया।

आलोचक कहेंगे कि भाजपा में आपकी कोई आवाज नहीं है। वहां केवल दो लोग हैं, पी.एम. मोदी और गृह मंत्री (अमित शाह)। उन्हें नहीं लगता कि यह सच है क्योंकि सभी सांसदों का एक संरक्षक मंत्री होता है। आप अपने राज्य में जो कुछ भी सामना कर रहे हैं, उसके बारे में उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा, आपके पास संगठन है..., यदि कुछ भी काम नहीं करता, चाहे आप इसे पसंद करें या न करें, संघ परिवार की नजरें और कान जमीन (जमीनी हकीकत) पर हैं। वह संघ परिवार से किसी व्यक्ति से नहीं मिलीं लेकिन उनके लिए बहुत स्पष्ट है कि संघ के बहुत वरिष्ठ, अनुभवी नेता संसदीय प्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसलिए बातचीत के बहुत सारे स्तर हैं। कांग्रेस में, यदि शीर्ष पर कोई आपसे नाराज हो जाता है, तो आपका करियर समाप्त हो जाता है। आप कांग्रेस में परिवार का मुकाबला नहीं कर सकते और जीवित (राजनीतिक रूप से) नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप भाजपा में एक योग्य व्यक्ति हैं, तो आपके लिए हमेशा एक मंच रहेगा।

भाजपा में संघ परिवार की भूमिका के बारे में सुष्मिता का कहना है, कांग्रेस पर भी एक परिवार का राज है। एक पार्टी गांधी परिवार के साथ है और भाजपा के लिए, उनका विचार संघ परिवार है। और एक बड़े संगठन जैसे आर.एस.एस. का होना बेहतर है, जहां अलग-अलग विचार हों, न कि केवल एक परिवार। परिवार तो दोनों तरफ है। उस तरफ एक 'पहला परिवार' है और इस तरफ, एक संघ परिवार है। लेकिन संघ परिवार कहीं अधिक लोकतांत्रिक है क्योंकि यह एक परिवार की तुलना में एक बड़ा संस्थान है। टी.एम.सी. छोड़ने बारे दास ने कहा कि तृणमूल में उनकी स्थिति किसी और जैसी नहीं थी क्योंकि वह बंगाल में जमीनी स्तर पर राजनीति करने वाली व्यक्ति नहीं थी। उन्हें लगा कि टी.एम.सी. नेता के लिए बंगाल के बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करना बेहद कठिन था। उनके पास कांग्रेस और भाजपा के बीच एक विकल्प था। उन्हें लगा कि जिस तरह से वे (भाजपा) पूर्वोत्तर राज्यों में काम कर रहे हैं, उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। असम के सी.एम. (हिमंत बिस्वा सरमा) और गृह मंत्री अमित शाह से बात करने के बाद, उन्हें स्पष्ट हो गया था कि यदि वह अपने लोगों के लिए अगले 10-15 वर्षों तक काम करना चाहती हैं, तो भाजपा ही वह पार्टी है।

छात्रों के विरोध प्रदर्शन से सरकार के निपटने के तरीके के बारे में सुष्मिता का कहना था कि मोदी सरकार ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, चाहे नया कानून लाकर हो, धर्मेंद्र प्रधान के कदम उठाने (सक्रिय होने) से हो, उन्होंने इसे अच्छी तरह से संभाला। अब जो मामला अदालत के विचाराधीन है, वह यह है कि वहां इस्तेमाल किया गया बल अनुपातिक और आवश्यक था या यह अनुचित (अत्यधिक) था। हालांकि, संसद की ओर मार्च करते हजारों लोगों को देखते हुए, क्या वे गेट पर रुक जाते? संसद की सुरक्षा करना भी गृह मंत्री की जिम्मेदारी है।

शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है कुंजल क्रिया

भारत में योग का चलन आज से नहीं बल्कि सदियों से रहा है। योग महज एक शारीरिक व्यायाम नहीं है। बल्कि यह जीवन को सरल और बेहतर बनाने का एक बेजोड़ तरीका है। आज हम आपको योगा की एक ऐसी ही टेक्निक से रूबरू कराएंगे। जो आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को तो बाहर निकालती ही है। साथ ही आपको कई दूसरे लाभ भी देती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कुंजल क्रिया के बारे में। यह अन्य योगासन से बहुत भिन्न है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस क्रिया में आपको उल्टी करनी होती है। हां शायद यह आपको थोड़ी अजीब लग सकती है। लेकिन कुंजल क्रिया सही मायने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आइए जानते हैं इस क्रिया के बारे में।

क्या आपने कभी कुंजल क्रिया के बारे में कुछ सुना है। अगर नहीं तो यह क्रिया आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। आइए जानते हैं कुंजल क्रिया के बारे में और जानते हैं कैसे यह आपकी सेहत पर असर डालती है।

क्या है कुंजल क्रिया

कुंजल क्रिया आपके शरीर से अशुद्धियां बाहर निकालने की एक जबरदस्त टेक्निक है। कुंजल क्रिया के बारे में सबसे पहले हठयोग से संबंधी एक प्रदीपिका ग्रंथ में दिया गया था। इस ग्रंथ में ही इसे शरीर की सफाई करने की तकनीक के रूप में बताया गया है। कुंजल क्रिया न केवल आपके शरीर को साफ करती है बल्कि यह आपके मन को भी नियंत्रित करने में भी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन में इसे लेकर एक शोध भी प्रकाशित किया गया है। इसमें बताया गया है कि उल्टी करने के बाद व्यक्ति को खालीपन महसूस होता है और इससे कई शारीरिक लाभ होते हैं। आइए जानते हैं कैसे की जाती है कुंजल क्रिया।

कैसे होती है कुंजल क्रिया

- इसके लिए आपको कम से कम 6 से 8 गिलास गुनगुने पानी की जरूरत होगी और हर एक लीटर पानी पर एक चम्मच सेंधा नमक या साधारण नमक भी चाहिए होगा।
- अब आपको एक लीटर पानी में एक चम्मच सेंधा नमक मिलाना होगा और कगासन की मुद्रा में बैठना होगा।
- इसके बाद आपको इसी मुद्रा में यह पानी जल्दी से जल्दी पीना होगा और उल्टी करने के लिए थोड़ा आगे झुक कर खड़ा होना होगा।
- जब आपको लगे की पेट खाली हो चुका है तो शवासन की मुद्रा में 30 मिनट के लिए लेट जाएं।
- इस क्रिया में आपको उल्टी तुरंत आ जाती है। ऐसे में अगर यह क्रिया करें तो विशेषज्ञ की निगरानी में ही करें।

वजन और पाचन के लिए

जब भी आप कुंजल क्रिया करते हैं तो इससे आपके पेट की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और फैट कम हो जाता है। ऐसे में अगर आप फैट या वजन कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं तो य क्रिया आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। यह पाचन तंत्र को पूरी तरह स्वस्थ रखने काम काम करती है।

तनाव और चिंता से राहत

जब आप इस क्रिया को करते हैं तो इससे शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर हो जाता है और आपके शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचने लगता है। इससे आपका हार्ट रेट कम हो जाता है और सांस लेना भी आसान हो जाता है। साथ ही यह ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कुंजल क्रिया के जरिए तनाव और चिंता को कम किया जा सकता है। ध्यान रहे कि यह क्रिया किसी विशेषज्ञ की

या फिर आपकी आयु 16 साल से कम है तो इस आसन को बिल्कुल ना करें।

खांसी और सर्दी से राहत

जब आप कुंजल क्रिया करते हैं तो इससे आपके फेफड़ों की मांसपेशियां मजबूत होती है और इनकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। साथ ही इसके जरिए आपके फेफड़े भी साफ हो जाते हैं और आपके लिए सांस लेना आसान हो जाता है। इस तरह यह सर्दी और खांसी के लक्षणों से राहत दिलाती है।

एलईडी और टीएफटी स्क्रीन से निकलने वाली सफेद रोशनी आंखों को तनाव में डालती है। आयुर्वेद के अनुसार, संपूर्ण शरीर की तरह आंख भी तत्वों से संबंधित है। आंख की मांसपेशियां पृथ्वी तत्व द्वारा नियंत्रित होती हैं, जबकि ब्लड वेसल्स अग्नि द्वारा और आंखों का रंग हवा से नियंत्रित होता है।

ऐसे करें आंखों की देखभाल

मोबाइल और लैपटॉप के बढ़ते इस्तेमाल के कारण हमारी आंखों का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा हो रहा है। जिससे लोगों में सिरदर्द, जलन और आंखों में तनाव के मामले बढ़े हैं। खासकर, एलईडी और टीएफटी स्क्रीन से निकलने वाली सफेद रोशनी आंखों को तनाव में डालती है। आयुर्वेद के अनुसार, संपूर्ण शरीर की तरह आंख भी तत्वों से संबंधित है। आंख की मांसपेशियां पृथ्वी तत्व द्वारा नियंत्रित होती हैं, जबकि ब्लड वेसल्स अग्नि द्वारा और आंखों का रंग हवा से नियंत्रित होता है। आंखें पित्त दोष का आसन हैं। चूंकि पित्त दोष उम्र के साथ असंतुलित हो जाता है, इसलिए आंखें प्रभावित होती हैं।

सुबह उठकर मुंह में पानी भरें

रोज सुबह उठकर टॉयलेट जाने से पहले या बाद में मुंह में पानी भरें और कुछ सैकंड्स तक होल्ड करें। इस दौरान आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। अब कुल्ला कर दें और इस प्रक्रिया को दो से 3 बार दोहराएं।

त्रिफला वॉटर का उपयोग करें

त्रिफला वॉटर आई वॉश आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यह न केवल आपके आंखों की रोशनी बढ़ाता है, बल्कि आंखों की चमक में भी सुधार करता है। खासतौर से थकी हुई आंखों को आराम देने का यह बेहतरीन तरीका है।

स्वस्थ आंखों के लिए षटकर्म करें

आयुर्वेद में शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने ,उसे मजबूत बनाने और रोगमुक्त बनाने के लिए 6 प्यूरीफिकेशन टेकनीक के बारे में बताया गया है। इनमें से नेती और त्राटक सूखी आंखों और आंखों के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे आयुर्वेदिक उपाय के रूप में काम करते हैं। बता दें कि त्राटक षटकर्म आंख का व्यायाम है जिसमें किसी भी बिंदु पर आंखों को स्थिर करके निरंतर देखना होता है।

बरतें ये सावधानियां

- आंखों की देखभाल के दौरान कभी भी बहुत तेज गर्म या फिर बर्फ के पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
- अचानक तापमान में हुए परिवर्तन से बचने का प्रयास करें।
- अगर आपका शरीर गर्म हो रहा है या आप पसीने से तर हैं, तो अपने चेहरे और आंखों पर पानी के छीटें मारने से पहले 10 मिनट तक इंतजार करें। जब तक आपकी बॉडी सही तापमान में एडजस्ट न हो जाए, छीटें मारने से बचें।
- सुबह-शाम चेहरे पर पानी के छीटे मारें
- 10-15 बार अपनी आंखों और चेहरे पर ठंडे या फिर नॉर्मल पानी के छीटें मारें। इस प्रक्रिया को आप तब भी दोहराएं , जब शाम को काम से वापस घर लौटें। ऐसा करने से आंखों को बहुत आराम मिलेगा।

स्वस्थ आंखों के लिए फायदेमंद है अंजन

स्वस्थ आंखों के लिए अंजन का उपयोग बहुत फायदेमंद है। अंजना एक आयुर्वेदिक दवा है, जिसे आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पलकों के अंदरूनी हिस्से पर लगाते हैं। बता दें कि अंजना जड़ी-बूटियों से बना एक गाढ़ा आईलाइनर है। इसे कोलिरिसम भी कहते हैं। इसका उपयोग आंखों की रोशनी बढ़ाने और आंख से जुड़ी अन्य बीमारियों के लिए किया जाता है। हालांकि, यह काजल की तरह दिखता है, लेकिन इससे काफी अलग है। इसे मिनरल्स और जड़ी- बूटियों को पीसकर पेस्ट के रूप में तैयार किया जाता है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए इनकी देखभाल करना बेहद जरूरी है। उम्मीद है यहां एक्सपर्ट द्वारा बताए गए तरीकों से आपको आंखों की सही देखभाल करने में मदद मिलेगी।

वायु प्रदूषण और रोड ट्रैफिक से पड़ता है सेहत पर बुरा असर

वायु प्रदूषण और रोड ट्रैफिक से हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन कई दफा हम इसे नजरअंदाज करते हैं। शोध में पता चला है कि ये दोनों पर्यावरण हार्ट फेलियर का भी एक कारण हैं।

देश में दिवाली आने वाली है और इस माह में लोगों द्वारा की जाने वाली आतिशबाजी के कारण वायु प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ जाता है और स्मॉग का रूप ले लेता है। इस तरह के पॉल्युटिड स्मॉग में धूल और वायु प्रदूषक जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाई आक्साइड, ज्वलनशील कार्बनिक यौगिक आदि हानिकारक मिश्रण रहते हैं। जो खांसी, गले में खराश, छाती में जलन, स्किन डिजीज, फेफड़ों के संक्रमण, आंख व नाक में एलर्जी के अलावा इम्यून सिस्टम को भी कमजोर बनाते हैं। हाल ही में वायु प्रदूषण पर एक शोध आया है जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नए शोध के अनुसार, वायु प्रदूषण और सड़क यातायात के शोर के संपर्क में आने से हृदय गति रुकने का खतरा बढ़ सकता है। शोध का रिजल्ट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के एक ओपन-एक्सेस जर्नल 'जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन' में प्रकाशित किया गया था। इसलिए आपको वायु प्रदूषण से खुद को सेफ रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है।

वायु प्रदूषण पर शोध

नए रिसर्च के विश्लेषण में शोधकर्ताओं ने 15 से 20 साल के पीरियड में लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट इंपैक्ट को लेकर हर्ट फेलियर की जांच की। डेनमार्क में महिला नर्सों पर हुए शोध में एयर पॉल्यूशन और रोड ट्रैफिक हर्ट फेलियर की मुख्य वजह पाया गया। बता दें कि शोध में जिन महिलाओं को लिया गया था उनकी उम्र 44 वर्ष और उससे अधिक थी। प्रतिभागियों को 1993 और 1999 में भर्ती किया गया था और जब उन्होंने नामांकन किया, तो हर महिला ने बॉडी मास इंडेक्स, लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे धूम्रपान, शराब का सेवन, शारीरिक गतिविधि और आहार संबंधी आदतों के अलावा अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में भी पूरी जानकारी दी थी। इन सभी प्रतिभागियों को डेनिश नेशनल पेशेंट रजिस्टर से लिंक करने के 20 साल के बाद हार्ट फेलियर के बारे में पता चला जिनका बाद में इलाज भी हुआ और इसके रिकॉर्ड भी हैं।

दिल के लिए ज्यादा खतरनाक है वायु प्रदूषण

डेनमार्क स्थिति कोपेहेगन यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े असिस्टेंट प्रोफेसर और शोध को लीड करने वाले ऑथर ने कहा कि स्टडी में पाया गया है कि तीन वर्षों में रोड ट्रैफिक का शोर 12 फीसदी हार्ट फेलियर के खतरे का कारण बना। उन्होंने आगे कहा, हम आश्चर्यचकित थे कि कैसे दो पर्यावरणीय कारक - वायु प्रदूषण और सड़क यातायात शोर ने एक साथ हृदय गति रुकने का जोखिम बढ़ा दिया है। शोध में पता चला है कि रोड ट्रैफिक की तुलना में एयर पॉल्युशन हर्ट फेलियर के खतरे की मजबूत वजह बना। हालांकि, इन हर्ट फेलियर वाली 30 प्रतिशत नर्सों में हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या थी।

सांस लेने में तकलीफ

वायु प्रदूषण की वजह से बुजर्ग लोगों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एयर पॉल्युशन के कारण बुजुर्गों के शरीर के कई अंग धीमी गति से कार्य करते हैं और इसी तरह का हाल फेफड़ों का रहता है। क्योंकि लंग्स प्रदूषित हवा को सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पाते हैं जिस वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है।

आंखों में परेशानी

वायु प्रदूषण के चलते कई बार बच्चों से लेकर बुजुर्गों की आंखों में भी दिक्कतें आती हैं। दूषिक हवा के कण हमारी आंखों में एलर्जी पैदा करने लगते है जिससे कई बार हमें आस-पास की चीजें साफ नहीं दिखती हैं। साथ ही धूल मिट्टी से आंखों में खुजली भी होती है।

सेहत संबंधी दिक्कतें

बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है जिसकी वजह से उनको वायू प्रदूषण और रोड ट्रैफिक से उनका दम घुटने लगता है। वे इस वातावरण को आसानी से हैंडल नहीं कर पाते। इसके चलते कई दफा, छींकआना, छाती में जलन, स्किन डिजीज, फेफड़ों के संक्रमण और गले में खराश जैसी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

साइलेंट किलर है तनाव, इसे गंभीरता से लेना है बहुत जरूरी

मेंटल हेल्थ एक पुराना विषय रहा है, लेकिन अब कोरोना के बाद यह और ज्यादा घातक हो गया है। अब इसे गंभीरता से लेकर इस पर बात करना जरूरी है। कोरोना ने कई तरह के मानसिक रोगों को जन्म दिया है

आज के दौर में हर शख्स अपनी जिंदगी में स्ट्रेस से गुजरता है। स्ट्रेस को आजकल एक कॉमन परेशानी के रूप में देखा जाता है और यही सबसे बड़ी गलती है। 2020 में आए कोविड 19 ने सोशल और इकोनॉमिक तौर पर काफी बदलाव लाया है। लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी गवां दी, यहां तक की एक दूसरे से मिलना-जुलना भी दूभर हो गया था। आज जहां 2021 में कोविड 19 को 2 साल हो गए हैं और आज भी मानव जाति इस विपदा से उबरने की कोशिश में है। कई देश आज भी इस वायरस के नए स्ट्रेन से लड़ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन ने ये चेतावनी जारी की है कि कोरोनावायरस का मेंटल हेल्थ पर काफी लंबे समय तक असर होता रहेगा। आज लोगों में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी कई समस्या बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं। इस पैंडेमिक के दौरान मेंटल हेल्थ पर गहरा असर पड़ा है। 2020 में माइसेंसी द्वारा एक सर्वे के आधार पर ठट्ठ के 75 प्रतिशत और एशिया के 33 प्रतिशत एम्प्लॉय में बर्न आउट के लक्षण दिखे हैं। यूरोपियन देशों में भी पैंडेमिक फैटिग के लेवल में बढ़ोतरी हुई है।

जिन लोगों ने अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत खराब रेट दिया है, उनकी मात्रा पैंडेमिक आने के बाद तीन गुना बढ़ गई है। ओरेकल और वर्क प्लेस इंटेलिजेंस जैसी कंपनियों द्वारा एक हालिया सर्वे जिसमें 11 देशों के 12000 लोगों ने भाग लिया ये दर्शाता है कि मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव में एम्प्लॉय के बदले ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज पाए गए हैं। 53% ने माना की उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज पैंडेमिक के शुरू होते ही शुरू हो गए थे। इसी कड़ी में 5 में से 4 मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव यानी लगभग 85% ने माना कि उन्हें काम को पूरा करने में दिक्कत आई। इसके कुछ कारण हैं जैसे घर से काम करने के दौरान नई तकनीक को समझने और उसका उपयोग करने में परेशानी और दूसरा यह कि ऑफिस के माहौल से दूर साथ बैठकर काम करने और कोलेबरेट करने की जगह घर से काम करना।

क्या कहती है रिपोर्ट?

इस कड़ी में लगभग 39% लोगों को घर से वर्चुअली काम करने में दिक्कत आई। वहीं 34% को वर्क कल्चर के ना होने की कमी खली। वहीं 29% लोगों को नई तकनीकों को समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। जहां एक तरफ कंपनी के सीनियर अधिकारी वर्कप्लेस पर मेंटल हेल्थ और हेल्थी वर्क कल्चर को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, वहीं आज भी मेंटल हेल्थ को एक स्टीरियोटाइप के तौर पर देखा जाता है। कंपनी में ओपन कम्युनिकेशन और सपोर्ट की कमी खलती है। कंपनी के लीडर को अपने स्टॉफ को न सिर्फ इंस्पायर करना चाहिए ताकि वे अपनी बात को खुलकर शेयर कर सकें, बल्कि उन्हें इंस्पायर भी करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर वे कोच या थेरेपिस्ट से मदद भी ले सकें। विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम को इग्नौर नहीं करना है, अगर तनाव से संबंधी कोई भी लक्षण नजर आता है तो तत्काल डॉक्टर से मिलना है। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते।

जान भी ले सकती है लौकी

लौकी का सेवन करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसे कई प्रकार से खा सकते हैं। सब्जी, जूस, खीर, कलाकंद, पराठे सहित अन्य तरीकों से इसका सेवन किया जा सकता है। इसका सेवन करने से कब्ज और गैस की समस्या में राहत मितली है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम,

कड़वी लौकी का सेवन करने से आपकी जान पर बात बन सकती

नौबत आ जाती है। इसलिए भूलकर भी कड़वी लौकी का सेवन नहीं करें। लौकी का जूस बनाने से पहले इसे जरूर टेस्ट करें। अगर वह कड़वी लगती है तो इसका सेवन नहीं करें। कड़वी विषैली लौकी का सेवन करने के नुकसान- बेचैनी, घबराहट, ब्लड प्रेशर की समस्या, उल्टी होने लगती है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कई बार अंगों पर भी इसका असर पड़ सकता है। ऐसे में अंग फैल भी हो सकते हैं। इसलिए भूलकर भी लौकी को टेस्ट किए बिना इसका प्रयोग नहीं करें। कड़वी लौकी की पहचान उसे चखकर की जा सकती है। बता दें कि इसे पकाने पर भी कड़वापन खत्म नहीं होगा। कड़वी लगने

डिफेंस सिस्टम विकसित कर लेती है। जिससे उसमें केमिकल विकसित हो जाता है। तो कई बार तापमान कम ज्यादा होने पर भी यह बदलाव होने लगते हैं। इतना ही नहीं पर्याप्त पानी नहीं मिलने पर भी ऐसा हो सकता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे सुखबीर बादल

चंडीगढ़। पंजाब की राजनीति में शुक्रवार को उस समय अचानक हलचल तेज हो गई जब शिरोमणि अकाली दल (बादल) के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने संसद भवन पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात को पंजाब की सियासत में अहम घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा चर्चा 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई है। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगा है कि क्या कभी पुराने सहयोगी रहे अकाली दल और भाजपा एक बार फिर चुनावी गठबंधन की राह पर लौट सकते हैं? पंजाब में 2027 का चुनाव आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल के बीच बहुकोणीय मुकाबले की तस्वीर पेश कर सकता है। भाजपा और अकाली दल के बीच संभावित तालमेल चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है। ग्रामीण और शहरी पंजाब में दोनों दलों के अलग-अलग प्रभाव क्षेत्रों को देखते हुए गठबंधन की स्थिति में मुकाबले के समीकरण बदल सकते हैं।

'जेन-जी' को किसी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं : प्रियंका गांधी

नईदिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत की एक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को कहा कि 'जेन-जी' को उनसे किसी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में भागवत की टिप्पणी से जुड़े सवाल पर संवाददाताओं से कहा, ''जेन-जी को मोहन भागवत जी से किसी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है।'' मोहन भागवत ने बृहस्पतिवार को कहा था कि लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन संवाद का एक वैध तरीका है, लेकिन इसका मकसद विभाजन पैदा करने के बजाय आम सहमति बनाना होना चाहिए। भागवत ने मुंबई में 'इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशन्स' (आईआईएमयूएन) के 15वें वर्षगांठ कार्यक्रम में 'जेन-जी' और 'जेन अल्फा' के लगभग 2,000 सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, ''विरोध प्रदर्शन भी बातचीत का एक तरीका है।

सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं। बबुआ भी यही करते थे। वो दोपहर 12 बजे सो कर उठते थे। दो बजे तैयार होते थे। पांच बजते-बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और शाम 7 बजे महफिल सज जाती थी। देश प्रदेश के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय ही कहां होता था। प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल तो ये था कि महिलाओं को सबसे बड़ा खतरा इन्हीं सपाइयों से ही था। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने का कि जब सरकारें प्रदेश के विकास के लिए काम करती हैं तो उसका लाभ समाज के हर तबके को मिलता है। इसके पहले सीएम योगी ने एक्स पर कहा कि आज उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत और हमारे कर्मठ बुनकर साथियों की अप्रतिम प्रतिभाओं को नमन करने का दिन है।

जेपीएससी को लेकर झारखंड विधानसभा में हंगामा

रांची। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं का मुद्दा सदन के अंदर और बाहर छाया रहा। विपक्षी दल भाजपा और आजसू ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई। भाजपा विधायकों ने छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच आवश्यक है। प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार छात्रों की मांगों के प्रति संवेदनशील नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्र पिछले 13 दिनों से सत्याग्रह पर बैठे हैं और कई छात्र भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार उनकी चिंता नहीं कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो वह सीबीआई जांच से क्यों बच रही है।

मुख्यमंत्री विजय और उदयनिधि स्टालिन में तीखी जुबानी जंग

चेन्नई। शुक्रवार को तमिलनाडु विधानसभा में कावेरी जल विवाद और कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध को लेकर मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के बीच तीखी बहस हुई। दोनों नेताओं ने सर्वदलीय बैठक और कर्नाटक के प्रति सरकार के रुख को लेकर एक-दूसरे पर सवाल उठाए। तमिलनाडु विधानसभा में इस मुद्दे पर बात करते हुए, स्टालिन ने मेकेदातु मामले पर विशेष ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की मांग की और सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे इस विवादित प्रोजेक्ट पर तमिलनाडु की एकजुटता दिखेगी। उदयनिधि ने पूछा कि मैं बस सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा हूं। कर्नाटक सरकार लगातार सर्वदलीय बैठकें कर रही है। हमारी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कर्नाटक द्वारा इस मुद्दे पर एकजुट रुख अपनाने के बावजूद, विजय के नेतृत्व वाली सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाने में हिचकिचा रही है। उन्होंने सवाल किया कि तमिलनाडु सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है।

एफसीआरए बिल पर 12 अगस्त को होगी चर्चा

संसद में गतिरोध दूर करने के लिए विपक्ष को मनाने में जुटी केंद्र सरकार

नईदिल्ली। संसद के सत्र के दौरान सरकार विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम को पास कराना चाहती है लेकिन विपक्ष के साथ गतिरोध को देखते हुए केंद्र ने बड़ा फैसला किया है। एफसीआरए (फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट) के लिए संसद में आगामी 12 अगस्त को चर्चा की तारीख तय की गई है और इसे पारित कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। यह बात तब कही गई जब केंद्र सरकार संसद में गतिरोध खत्म करने और मौजूदा मॉनसून सत्र के दौरान अहम विधेयकों पर चर्चा के लिए कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष के साथ बातचीत कर रही है।

मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा, मिजोरम के चर्च नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शाह से मिले ताकि प्रस्तावित कानून के बारे में अपनी चिंताएं जाहिर कर सकें। इस प्रस्तावित कानून का मकसद विदेशी फंडिंग वाली संस्थाओं पर निगरानी को और कड़ा करना है। इसके तहत एक शक्तिशाली अधिकृत संस्था (designated authority) बनाई जाएगी जो उन एनजीओ की संपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी जिनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो जाता है।

लालदुहोमा ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, हमने नए एफसीआरए विधेयक को लेकर अपनी आशंकाएं गृह मंत्री के सामने रखीं। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि यह विधेयक पिछली तारीख से लागू नहीं होगा।

कानून के समय-सीमा के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शाह ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में बहस होगी। यह प्रस्तावित कानून 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था।

गृह मंत्री को सौंपे गए एक ज्ञापन में, लालदुहोमा, मिजोरम कोहरान हरुआइतु कमिटी के चेयरमैन जॉन राल्डोसांगा और काउंसिल ऑफ चर्चेज इन मिजोरम के जनरल सेक्रेटरी लालहमांगाइहा ने केंद्र से आग्रह किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कानून केवल भविष्य के लिए लागू हो।

उन्होंने तर्क दिया कि पिछली तारीख से लागू करने पर कानूनी अनिश्चितता पैदा हो सकती है और वास्तविक संस्थाओं को पिछली प्रक्रियात्मक खामियों के लिए दंड का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम कोहरान हरुआइतु कमिटी और काउंसिल ऑफ चर्चेज इन मिजोरम, मिजोरम में प्रमुख चर्च समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफसीआरए संशोधन विधेयक में क्या प्रस्ताव है?

इस विधेयक का मकसद एक अधिकृत संस्था के माध्यम से विदेशी योगदान और संपत्तियों की निगरानी, प्रबंधन और निपटान के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करना है।

प्रस्तावित कानून के तहत, जिस संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है, सरेंडर कर दिया जाता है या खत्म हो जाता है, उसके विदेशी योगदान और ऐसे फंड से बनाई गई संपत्तियां, रद्द होने, सरेंडर करने या खत्म होने की तारीख से अस्थायी रूप से अधिकृत संस्था के अधिकार में आ जाएंगी।

अगर संस्था तय समय के भीतर नया रजिस्ट्रेशन हासिल करने या अपना लाइसेंस बहाल करने में विफल रहती है, तो वे विदेशी योगदान और संपत्तियां स्थायी रूप से अधिकृत संस्था को हस्तांतरित कर दी जाएंगी।

संसद में गतिरोध को खत्म करने की कोशिशों के तहत, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्तावित महिला आरक्षण और परिसीमन बिल के लिए समर्थन मांगने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संपर्क किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिजिजू ने गुरुवार को गांधी से फोन पर बात की - जो हाल के दिनों में ऐसी दूसरी बातचीत थी - और संसद के सुचारू कामकाज पर चर्चा करने के लिए पिछले 10 दिनों में उनसे दो बार मुलाकात भी की।

रिजिजू ने पत्रकारों से कहा, राहुल गांधी के साथ मेरी सार्थक बातचीत हुई। मैंने कुछ खास मुद्दों पर अनुरोध किया और अन्य मामलों पर भी चर्चा की। हम कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ लगातार बातचीत और समन्वित कार्रवाई की उम्मीद करते हैं।

सूत्रों के अनुसार, गांधी ने समर्थन देने से पहले प्रस्तावित कानून पर सर्वदलीय बैठक की कांग्रेस की मांग दोहराई। हालांकि, रिजिजू ने ऐसी बैठक बुलाने का कोई वादा नहीं किया।

सरकार प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन पर आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है, जो 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू करेगा।

रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रीय हित में सहयोग के रास्ते में राजनीतिक मतभेद नहीं आने चाहिए।

उन्होंने कहा, हम राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन नहीं हैं। इसलिए, हमें राष्ट्रीय हित में मिलकर काम करना चाहिए। हालांकि, बाहर यह धारणा बनती है कि वे संसद को बिल्कुल भी काम नहीं करने देने पर अड़े हैं; लेकिन आखिरकार इससे नुकसान किसका होता है?

सदन में अमित शाह की मौजूदगी की विपक्ष की मांग का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री नियमित रूप से संसद में आते रहे हैं और जब भी उनके द्वारा पेश किए गए कानून पर चर्चा होती है, तो वे मौजूद रहते हैं।

सरकार संविधान (131वां संशोधन) बिल को फिर से पेश करने की संभावना पर एनडीए सहयोगियों और समाजवादी पार्टी और डीएमके सहित अन्य विपक्षी दलों के साथ भी परामर्श कर रही है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया के माध्यम से लोकसभा की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 सीटें करना है, जिससे 2029 के आम चुनावों से पहले महिला आरक्षण को लागू करने का रास्ता साफ हो सके।

विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदन सोमवार तक स्थगित

खड़गे के दावे पर किरेन रिजिजू का तीखा वार

नईदिल्ली। विपक्ष द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर बयान की मांग के मद्देनजर नारेबाजी के बीच संसद के दोनों सदनों को 10 अगस्त को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में हंगामे के बीच राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्ताधारी और विपक्षी दोनों पक्षों से बैठने का आग्रह किया। प्रश्नकाल के दौरान सदन को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया।

लोकसभा में किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष यह तय नहीं कर सकता कि कौन सा मंत्री सदन में कब आए। निचले सदन में कड़े शब्दों में जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का नाम सुनकर आतंकवादी कांपते हैं। उन्होंने कहा कि जब चर्चा शुरू होगी, तो आप सुन नहीं पाएंगे। वह लंबे समय तक संसद में रहते हैं। विपक्ष यह तय नहीं कर सकता कि कौन सा मंत्री आएगा। संबंधित मंत्री सदन में मौजूद हैं।

उच्च सदन की मंजूरी के बाद, लोकसभा ने शुक्रवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया। यह विधेयक एमएसएमई के मुफ्त और स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को अधिसूचित करने का प्रावधान करता है; राज्य सरकारों को उनके गठन को तर्कसंगत बनाकर अतिरिक्त सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदें स्थापित करने में मदद करता है; और कुछ प्रावधानों के उल्लंघन से जुड़े अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है, जिसमें दोषी ठहराए जाने पर लगने वाले जुर्माने की जगह अलग-अलग स्तर के दंड का प्रावधान है और पहली बार उल्लंघन पर चेतावनी देने की व्यवस्था शामिल है।

उच्च सदन में, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहराई और दावा किया कि अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने अमित शाह को निर्देश जारी किया था; हालाँकि, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस दावे का खंडन किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि आपने (सभापति ने) गृह मंत्री से सदन में आकर बयान देने को कहा था। लेकिन वे (सत्ता पक्ष के सदस्य) आपकी बात का सम्मान नहीं कर रहे हैं और सदन का अपमान कर रहे हैं। किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष यह तय नहीं कर सकता कि कौन सा मंत्री कब सदन में आएगा। संसद में न आने के आरोपों के बीच, उन्होंने दावा किया कि गृह मंत्री शाह रोज़ाना संसद परिसर आते हैं।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने शुक्रवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों, विशेषकर छात्राओं के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किया गया और इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में विस्तृत बयान दें। उन्होंने अपने नोटिस में कहा कि प्रदर्शन को हटाने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन और कथित तौर पर पेलेट गन के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। उन्होंने पूछा कि पुलिस कार्रवाई का आदेश किसने दिया, क्या यह कानून और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप थी तथा कितने छात्र घायल, हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए।

खेल
प्रमुख समाचार

जूनियर एशिया कप के लिए पुरुष हॉकी टीम का ऐलान

नई दिल्ली। डिफेंडर अनमोल एक्का 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन के मोकी में होने वाले एएचएफ (एशियन हॉकी महासंघ) जूनियर एशिया कप में 18 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व करेंगे। हॉकी इंडिया के चयनकर्ताओं ने अर्जुन संतोष हरगुडे और रितिक लाकड़ा को टूर्नामेंट के लिए दो वैकल्पिक खिलाड़ियों के रूप में भी नामित किया है।

भारतीय टीम अभी बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्र में नवनियुक्त कोच फ्रेडरिक सोयेज के मार्गदर्शन में अभ्यास कर रही है। भारतीय टीम ने एशिया कप की तैयारी के सिलसिले में हाल में बेल्जियम का दौरा भी किया था। कोच सोयेज ने एक विज्ञप्ति में कहा, जूनियर एशिया कप के लिए चुनी गई टीम बेहद संतुलित है। खिलाड़ियों ने पिछले कुछ महीनों में कड़ी मेहनत की है। खिलाड़ियों का चयन लगातार अच्छे प्रदर्शन, सकारात्मक रवैये और दबाव में हमारी रणनीति पर अमल करने की क्षमता के आधार पर किया गया है।

उन्होंने कहा, एशिया कप में हमें कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। हम अनुशासित और आक्रामक हॉकी खेलने पर ध्यान देंगे और अपनी रणनीति पर अच्छी तरह से अमल करने की कोशिश करेंगे।

टीम : गोलकीपर- विवेक लाकड़ा, कुणाल तेवतिया। डिफेंडर- अनमोल एक्का (कप्तान), रोहित कुल्लू, चिराग, रविंदर, आशु मौर्य, संजीत टिर्की, सुखविंदर। मिडफील्डर- अड्रोहित एक्का, हरपाल, जीतपाल, मनमीत सिंह राय फॉरवर्ड- अजीत यादव, प्रभदीप सिंह, गुरसेवक सिंह, आर्यन जेस, लोवेनूर सिंह। स्टेंडबॉय खिलाड़ी- अर्जुन संतोष हरगुडे, रितिक लाकड़ा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 456 अंक टूटा निफ्टी 24,600 के नीचे बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को गिरावट के साथ कारोबार बंद हुआ। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली ने बाजार पर दबाव बनाया। इसके चलते निफ्टी50 65.35 अंक यानी 0.27 फीसदी गिरकर 24,570.65 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, सेंसेक्स 455.59 अंक यानी 0.58 फीसदी की गिरावट के साथ 78,499.17 पर बंद हुआ। निफ्टी50 इंडेक्स में बजाज फाइनेंस, बजाज Finserv और ट्रेंट सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल रहे। इन शेयरों में कमजोरी का असर भी बेंचमार्क इंडेक्स पर देखने को मिला। व्यापक बाजार की बात करें तो बड़े शेयरों की तुलना में मिडकैप इंडेक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी मीडकैप में 0.22 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। दूसरी ओर, निफ्टी स्मालकैप 0.05 फीसदी की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ।

हीरो मोटोकॉर्प का अप्रैल-जून तिमाही में शुद्ध लाभ घटा

नई दिल्ली। दोपहिया वाहन विनिर्माता हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 16.86% घटकर 1,417.93 करोड़ रुपए रह गया। वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में कंपनी ने 1,705.65 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया था। कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लाभ में सहयोगी कंपनियों में उसके निवेश की हिस्सेदारी आईपीओ और निजी नियोजन के बाद घटने से प्राप्त 722 करोड़ रुपए का एकमुश्त लाभ भी शामिल था। इसी कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजों पर उच्च आधार प्रभाव पड़ा। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी एकीकृत परिचालन आय बढ़कर 13,126.35 करोड़ रु. हो गई, जो 2025-26 की समान तिमाही में 9,727.75 करोड़ रु. थी।

ट्रेंट का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 22 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। टाटा समूह की खुदरा कंपनी ट्रेंट लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 22 प्रतिशत बढ़कर 518.07 करोड़ रुपए हो गया। वेस्टसाइड, जूडियो और स्टार ब्रांड के तहत खुदरा स्टोर संचालित करने वाली कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 424.70 करोड़ रुपए था। कंपनी की परिचालन आय जून तिमाही में 17.84 प्रतिशत बढ़कर 5,754.71 करोड़ रुपए हो गई। इस दौरान कंपनी का कुल खर्च 16.3 प्रतिशत बढ़कर 5,082.96 करोड़ रुपए हो गया। वेस्टसाइड के ऑनलाइन कारोबार और टाटा न्यू मंच पर उसकी मौजूदगी में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई। पहली तिमाही में वेस्टसाइड के कुल राजस्व में ऑनलाइन कारोबार की हिस्सेदारी छह प्रतिशत से अधिक रही।

मुंबई में लग्जरी घरों की बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड

मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लग्जरी हाउसिंग बाजार ने वर्ष 2026 की पहली छमाही में नया रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया सोथेबीज़ इंटरनेशनल रियल्टी और सीआरई मैट्रिक्स की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, ?10 करोड़ और उससे अधिक कीमत वाले घरों की कुल बिक्री 18,512 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे बड़ा अर्धवार्षिक आंकड़ा है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आने वाली तिमाहियों में बिक्री की रफ्तार कुछ धीमी पड़ सकती है। इसकी वजह एच1 2026 का बेहद ऊंचा आधार और आर्थिक विकास एवं शेयर बाजार को लेकर अधिक सतर्क दृष्टिकोण बताया गया है। जनवरी से जून 2026 के बीच 957 लग्जरी घरों की बिक्री हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है।

आरबीआई को नीतिगत दरों में बढ़ोतरी करने की कोई जल्दी नहीं

तमाल बंद्योपाध्याय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अगस्त की मौद्रिक नीति में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केंद्रीय बैंक की दर निर्धारण संस्था, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने वित्त वर्ष 2027 की अपनी तीसरी द्विमासिक बैठक में नीतिगत दर को 5.25 फीसदी पर अपरिवर्तित रखा है। बुधवार को समाप्त हुई बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। मौद्रिक नीति के रुख में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, यह तटस्थ बनी हुई है।

आरबीआई गवर्नर के बयान में आगे के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं दिया गया है क्योंकि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून, अल नीनो, भू-राजनीति और वैश्विक व्यापार नीति से संबंधित अनिश्चितताओं के कारण दृष्टिकोण 'अस्पष्ट' है। हालांकि, वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी वृद्धि और मुद्रास्फीति, दोनों के अनुमानों में बदलाव हुए हैं। आरबीआई ने इस वर्ष के लिए अपने आ?र्थिक वृद्धि पूर्वानुमान को 10 आधार अंक (बीपीएस) बढ़ाकर 6.7 फीसदी कर दिया है और मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को भी 10 आधार अंक घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। 10 बीपीएस की यह बढ़ोतरी पहली और दूसरी तिमाही के आर्थिक वृद्धि अनुमानों में संशोधन के कारण हुई है, जबकि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही के आ?र्थिक वृद्धि अनुमान में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

आरबीआई के जून के अनुमान की तुलना में पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि अनुमान को 40 बीपीएस बढ़ाकर 7 फीसदी और दूसरी तिमाही के लिए 10 बीपीएस बढ़ाकर 6.4 फीसदी कर दिया गया है। तीसरी तिमाही के लिए वृद्धि अनुमान 6.5 फीसदी और चौथी तिमाही के लिए 6.8 फीसदी पर अपरिवर्तित है। जून में गवर्नर के बयान में कहा गया था, 'वैश्विक

आपूर्ति श्रृंखला में लंबे समय तक व्यवधान, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और मौसम संबंधी झटके घरेलू आ?र्थिक वृद्धि के दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करते रहते हैं।' नवीनतम बयान के अनुसार, 'जोखिम संतुलित हैं।' इसमें वित्त वर्ष 2028 की पहली तिमाही में 7.3 फीसदी की वृद्धि का अनुमान भी लगाया गया है।

पहली तिमाही में मुद्रास्फीति 3.9 फीसदी रही, जो आरबीआई के जून के अनुमान 4.2 फीसदी से कम है। केंद्रीय बैंक ने दूसरी तिमाही के मुद्रास्फीति अनुमान को 40 आधार अंक घटाकर 4.7 फीसदी कर दिया है। तीसरी तिमाही का अनुमान 5.9 फीसदी पर अपरिवर्तित रखा गया है जबकि चौथी तिमाही का अनुमान 10 आधार अंक बढ़ाकर 5.5 फीसदी कर दिया गया है।

जून के अनुमानों में 'ऊपर की ओर जोखिम' की चेतावनी शामिल थी, लेकिन नवीनतम अनुमानों में जोखिम संतुलित हैं। आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2028 की पहली तिमाही के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 5.3 फीसदी है।

नीतिगत वक्तव्य में यह स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि आम मुद्रास्फीति का दबाव मामूली बना हुआ है, फिर भी खाद्य पदार्थों, ईंधन और अन्य इनपुट की कीमतों में वृद्धि के कारण व्यापक मुद्रास्फीति होने का खतरा बना हुआ है। आरबीआई सतत विकास को बढ़ावा देने और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास करेगा। अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी कब देखने को मिलेगी? आरबीआई के मुद्रास्फीति अनुमान के अनुसार, यदि नीतिगत ब्याज दर नहीं बढ़ाई गई तो तीसरी तिमाही से वास्तविक दर ऋणात्मक हो जाएगी।

वास्तविक दर, जिसे आमतौर पर वास्तविक ब्याज दर या वास्तविक रिटर्न दर कहा जाता है, एक वित्तीय मापक है जो क्रय शक्ति में वास्तविक परिवर्तन को दर्शाने के लिए मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित दर को बताता है। अनुमान के अनुसार, तीसरी और चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति क्रमश: 5.9 फीसदी और 5.6 फीसदी रहने की उम्मीद है, जबकि नीतिगत दर 5.25 फीसदी है।

क्या दिसंबर में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होनी चाहिए और इससे पहले अक्टूबर में नीतिगत रुख में बदलाव होना चाहिए? फिलहाल इसका अनुमान लगाना मुश्किल है।

सुरक्षा, संबल और सम्मान से संवर रहा छत्तीसगढ़

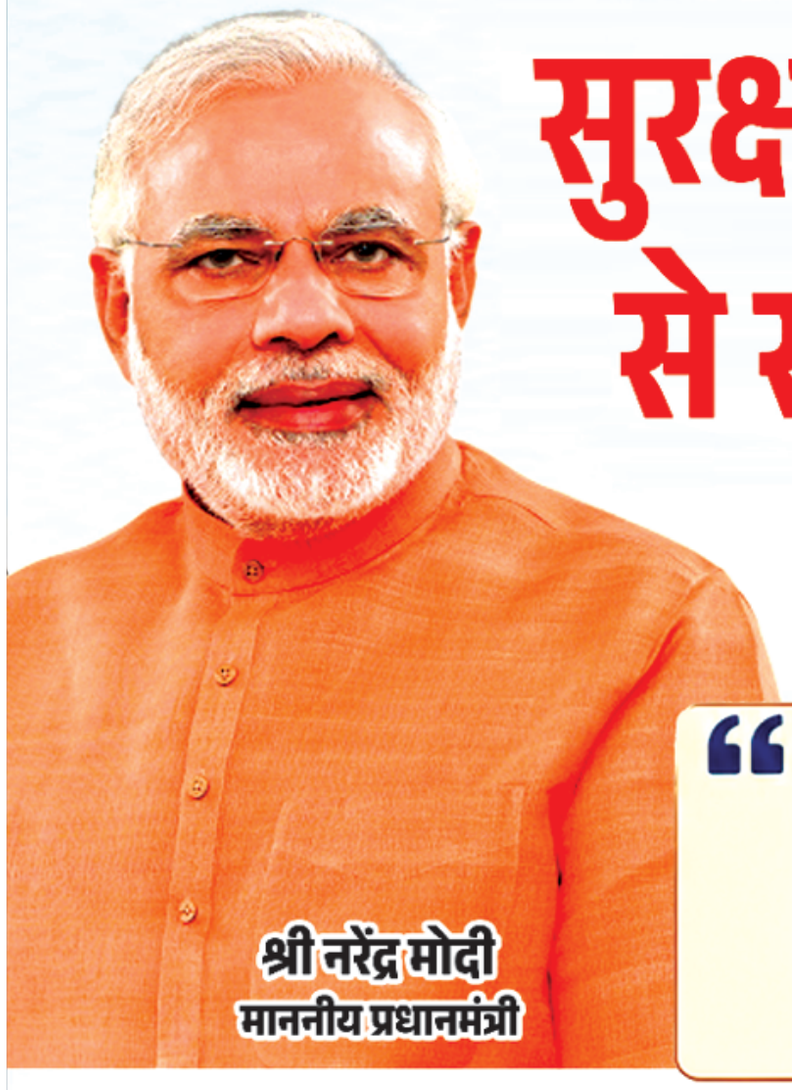

श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

खाद्य सुरक्षा, मुफ्त राशन और तकनीक आधारित सुशासन से सशक्त हो रहा छत्तीसगढ़

> हमारा संकल्प है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित न रहे। आधुनिक तकनीक, पारदर्शी वितरण प्रणाली और गरीब कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के साथ हम हर जरूरतमंद तक राशन, पोषण और योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। मुफ्त चावल से लेकर स्मार्ट पीडीएस और सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान तक, हमारा लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक सुशासन की गारंटी पहुंचाना है।

– विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा अब केवल राशन वितरण की व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, जनकल्याण और सुशासन का मजबूत आधार बन चुकी है। वर्ष 2026 में राज्य सरकार ने गरीब परिवारों, किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं विकसित की हैं जिनसे खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा दोनों को नई मजबूती मिली है। मुफ्त चावल, पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तकनीक आधारित निगरानी, श्रमिक कल्याण और सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान जैसे कदमों ने राज्य को जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का मॉडल बनाया है।

सुथार छत्तीसगढ़ अभियान के समाधान शिविर में योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हितग्राही

मुफ्त राशन की गारंटी से मजबूत हुई खाद्य सुरक्षा

अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के लाखों परिवारों को राज्य सरकार द्वारा कई वर्षों तक निःशुल्क चावल उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक निर्णय।

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राज्य की खाद्य सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी समन्वय।
- चावल, नमक तथा आवश्यक खाद्य सामग्री की नियमित उपलब्धता से घरेलु खर्च में कमी।
- पोषण सुरक्षा को सशक्त कर समुद्ध और स्वस्थ छत्तीसगढ़ की दिशा में बड़ा कदम।

हर परिवार तक पहुंच रही पोषण सुरक्षा

खाद्य सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य केवल अनाज उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि पोषण सत्र में सुधार लाना भी है।

- महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और खाद्य विभाग के समन्वित प्रयास।
- आदिवासी, दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में विशेष ध्यान।
- कुपोषण की रोकथाम और स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में मजबूत पहल।

सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियानः योजनाओं का एकीकृत लाभ

विभिन्न विभागों की योजनाओं को एक मंच पर लाकर पात्र परिवारों तक शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने की अभिनव पहल।

- परिवारों के जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक समानता को नई गति।
- अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आवास, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, कृषि सहायता और नागरिक सेवाओं सहित 31 प्रमुख योजनाओं को जोड़ा गया है। इससे परिवारों की पात्रता, लाभ और योजनाओं की प्रगति की जानकारी एकीकृत रूप से उपलब्ध हो रही है तथा संतृप्तिकरण की दिशा में तेजी आई है।

स्मार्ट पीडीएसः पारदर्शिता और तकनीक का नया अध्याय

***SARTHAK PDS Phase-2** के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह आधुनिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा रहा है।*

- AI, GPS ट्रैकिंग, QR कोड टैगिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग से वितरण प्रणाली में पारदर्शिता।
- आधार प्रमाणीकरण, ई-केवाईसी और वन नेशन वन राशन कार्ड से कहीं भी राशन प्राप्ति की सुविधा।
- अनियमितताओं पर नियंत्रण और लाभ का सीधा हस्तांतरण पात्र परिवारों तक।

2026 में
68 लाख +
पात्र हितग्राही परिवारों को निःशुल्क राशन का लाभ

किसानों की समृद्धि से मजबूत हुई अन्न सुरक्षा

किसानों को बेहतर मुल्य, तकनीकी सहायता और प्रत्यक्ष भुगतान से कृषि क्षेत्र में आई समृद्धि ।

- समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और प्रति क्विंटल 3100 रुपए की दर से भुगतान।
- 25 लाख + किसानों के खातों में हजारों करोड़ रुपये की अंतर राशि का प्रत्यक्ष भुगतान।
- उन्नत खेती, ड्रोन तकनीक, नैनो उर्वरक, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और एफपीओ के माध्यम से आय वृद्धि।

₹3100
प्रति क्विंटल धान
25 लाख+
किसान लाभान्वित

श्रमवीरों को सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक संबल

श्रमिकों के कल्याण, सुरक्षा और सम्मान के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता।

- दीदी ई-रिस्शा सहायता योजना में बढ़ी सहायता राशि।
- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना में सहयोग राशि में वृद्धि ।
- निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, छात्रवृति, सुरक्षा उपकरण सहायता और DBT के माध्यम से सीधा लाभ।
- लाखों श्रमिक परिवारों को मिला आर्थिक संबल।

31 प्रमुख योजनाएं
एक मंच | एक लाभार्थी | एकीकृत सेवा

प्रमुख उपलब्धियां

- मुफ्त चावल की निरंतर उपलब्धता
- AI, GPS, QR आधारित स्मार्ट पीडीएस
- किसानों को समर्थन मूल्य और DBT भुगतान
- श्रमिकों के लिए बढ़ी सहायता और सुविधाएँ
- सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान से योजनाओं का एकीकरण
- पारदर्शी, जवाबदेह सुशासन व्यवस्था

संकल्प हमारा – कोई भूखा न सोए, हर थाली में अन्न हो, हर हाथ को सम्मान हो

संवाद-48628/1

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.